लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त ग्रनूदित संस्करण SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

चौवहवां सत्र
Fourteenth Session

5th Lok Sabha



संड 53 में ग्रंक 1 से 10 तक हैं Vol. LIII contains Nos. 1 to 10

लोक-सभा सिवालय नई दिल्ली LOK SABHA SECRETARIAT NEW DELHI

मृत्य : वो रुपये Price ; Two Rupees

विवयः सूची/CONTENTS

ग्रंक 13, बुचवार, 6 ग्रगस्त, 1975/15 श्रावण, 1896 (शक)

No. 13, Wednesday, August 6, 1975/Sravana 15, 1897 (Saka)

विषय	Subject	PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्न	Papers laid on the Table	1-2
सभा की बैठकों से सदस्यों की ग्रनुपस्थिति सम्बन्धी समिति∍कार्यवाही सारिश	Committee on Absence of Members from sittings of the House—Minutes	3
सभा की बैठकों से सदस्यों की अपनुप्रिति	Leave of Absence of Members from sittings of the House	.3
संसद सदस्यों के वेतन ग्रौर भत्ते (संशोधन) विधेयक—-पुरः- स्थापित	Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill—Introduced	374
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	4
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah	4
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	5
पं० डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	5
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	5-6 6
श्री के० हनुमन्तैया श्री ग्रार० वी० स्वामीनाथन	Shri R. V. Swaminathan	6-7
	Shri Mohan Dharia.	
श्री मोहन धारिया		7
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट श्री एस० ए० कार्दर	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	7 7—9
खण्ड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1	10—11
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	11
श्रों मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	11
डा० कैलास	Dr. Kailas	11-12
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	12
सीमा शुल्क टेरिक विधेयक	Customs Tariff Bill	12
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as reported by Select Committee.	12
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee .	12-13

विषय	Subject	l'AGES
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali	13-14
श्री ग्ररविन्द बाल पजनौर	Shri Arvind Bala Paianor	14-15
खण्ड 2 से 13 तथा 1	Clauses 2 to 13 and 1	17
पारित करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में	Motion to pass, as reported by Select Committee	17
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali	17
श्री डो० डो० देसाई	Shri D. D. Desai	17-18
श्री चवलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chaplendu Bhattacharyyia .	īß
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	18
विश्वविद्यालय स्रनुदान स्रायोग के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन	Motion Re. Annual Report of University Grants Commission for 1972-73	19
के बारे में प्रस्ताव	Prof. S. Nural Hasan	19-20
प्रो० एस नुरूल हसन श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	2022
श्री सुधाकर पाण्डेय	Shri Sudhakar Pandey .	22-23
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shanker Dayal Singh .	23-24
त्रा अकर दयाल ।सह प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar .	24-25
श्री जी० विक्वनाथन	Shri G. Viswanathan	25-26
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh .	26
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	27
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	. 27-28
श्री मोहम्मद जमीलुरेहमान	Shri Md. Jamillurrahman .	. 28-29
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki .	29-30
श्री ग्ररबिन्द वाल पजनौर	Shri Arvinda Bala Pajanor .	30
श्री पो० एथतः रेड्डः	Shri P. Antony Reddy .	30-31
श्री पी गंगा रेड्डी	Shri P. Ganga Reddy	31-32
श्रीमती रोजा देशपंडि	Shrimati Roza Deshpande .	32
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	32-33
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh .	33-34
श्री बी० ग्रार० शुक्ल	Shri B. R. Shukla .	• 34
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	34-35

्रस्र_{िकनीडू}, श्री मगन्ती (गुडिवाडा) ग्रग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद) अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द) ग्रचल सिंह, श्री (ग्रागरा) ग्रजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर) श्रंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव) - ग्रप्पालानायडु, श्री (ग्रनकपल्ली) म्ब्रम्बेश, श्री (फिरोजाबाद) -ग्ररविन्द नेताम, श्री (कांकेर) ंग्रलगेशन, श्री ग्रो० वी० (तिरुत्तनी) म्रवधेश चन्द्र सिंह (फरुखाबाद) म्ब्रहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

ग्रा

ं**ग्रागा, श्री सैयद ग्रहमद (बारामूला)** ब्राजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर) न्त्रानन्द सिंह, श्री (गोंडा) म्रास्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट) ्इस्माइतः, हुसैन खां श्री (वारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला) उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा) ंडरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा) उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी) ्उलगनबी, श्री ग्रार० पी० (वैल्लौर)

Ų

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित ग्रांग्ल भारतीय) एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़) कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना) कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव) कडनापल्ली: श्री रामचन्द्रन (कासरगोड) कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम) कदम, श्री जे० जी० (वर्धा) कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले) कपूर, श्री सतपाल (पटियाला) कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ) कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर) कर्ण सिंह डा० (अधमपुर) कर्णी सिंह डा० (बीकानेर) कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूचिरापल्ली) कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची) कस्तुरे, श्री ए० एस० (खामगांव) कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण) कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर) काबले, श्री टी० डी० (लातुर) काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पंजिम) कामरांज, श्री के० (नागरकोइल) कामाक्षेया, श्री डी० (नेल्लोर) काले, श्री (जालना) कावड़े, श्री वी० ग्रार० (नासिक)

काहनडोल, श्री (मालेगांव) किन्दर लाल, श्री, (हरदोई) किरुतिनन, श्री था (शिवगंज) किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम) कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट) कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (ग्रनन्तनाग) कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व) क्शोक, बाकुला, श्री (लहाख) केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर) कैशाल, डा० (बम्बई दक्षिण) केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड) कोत्राशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव) कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी) कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ) कृष्णन, श्री ई० ग्रार० (सलेम) कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि) कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार) कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बट्र) कृष्णप्पा. श्री एम० वी० (हस्कोटे) कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधन्र)

ख

खाडिलकर, श्री ग्रार० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (ग्रंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० ग्रार० (ग्रन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा) गायती देवी, श्रीमती (जयपुर) गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल) गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह) गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजापुर) गुप्त, श्रो इन्द्रजीत (ग्रलीपुर) गुह, श्री समर (कन्टाई) गेंदा सिंह, श्री (पदरोना) गोखले, श्री एच० ग्रार० (बम्बई उत्तर पश्चिम) गोटखिन्डे, श्री ग्रण्णासाहिब (सांगली) गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट) गोदरा, श्री मनीराम (हिसार) गोपाल, श्री के० (करूर) गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट) गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट) गोयन्का, श्री ग्रार० एन० (विदिशा) गोस्वामी, श्री दिनेश: चन्द्र (गोहाटी) गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप) गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित ग्रासाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र) गोडफ़े, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित ग्रांग्ल भारतीय) गौडर, श्री जे॰ माता (नीलगिरी) गौडा, श्री पम्पन (रायच्र) गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट) घ घोष, श्री पी० के० (रांची) च चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा) चटर्जी, श्री सोमनाथ (वर्दबान) वत्वंदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी०
(शिमोगा)

चन्द्राकर, श्री चन्द्रलाल (दुर्ग) चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया) चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़) चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा) चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन) चिक्क लिंगैया, श्री के० (मांडया) चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट) चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्त्र) चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी) चौधरी श्री ग्रमर सिंह (मांडवली) चौधरी, श्री ईश्वर (गया) चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपूर) चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद) चौधरी, श्री बी० ई.व. (बीजापुर) चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी) चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

ন্ত

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर) छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (तिचूर)
जमीलुरेहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयशक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)

जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाह।जहांपुर)
जुल्फिकार श्रली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंटा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (ग्रान्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर) ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली) डाडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापिल्ल)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० वे० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम) दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम) दंडवते प्रो॰ मधु (राजापुर) दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर) दलबीर सिंह, श्री (सिरसा) दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली) दाम णी, श्री एस० ग्रार० (शोलापुर) दास, श्री ग्रनादि चरण (जाजपुर) दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी) दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर) दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार) दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर) दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़) दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा) दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सोतापुर) दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची) दुमादा, श्री एल० के० (डहानू) दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा) दुराईरास्, श्री ए० (पैरम्बूलुर)

देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (तिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (ग्रमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद) धामनकर, श्री (भिवंडी) धारिया, श्री मोहन (पूना) धूसिया, श्री ग्रनन्त प्रसाद (बस्ती) धोटे, भी जांबुबंत (नागपुर)

Ħ

नन्द, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री ग्रमृत (बाड़मेर)
निवालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर) पंडित, श्री एस० टी० (भीर) पजनौर, श्री ग्ररविन्द बाल (पांडीचेरी) पटनौयक, श्री जे० बी० (कटक) पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी) पटेल, श्री ग्ररविन्द एम० (राजकोट) पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका) पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना) पटेल, कुमारी मणिवेन (साबरकंठा) पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार) पटेल, श्री प्रभदास (डाभोई) पटेल, श्री ग्रार० ग्रार० (दादर तथा नगर हवेली) पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल) परमार, श्री भालजीभाई (दोहद) पालोडकर, श्री मानिकराव (ग्रौरंगाबाद) पास्वान, श्री राम भगत (रासेरा) पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन) पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद) पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेनपुर) पांडे, श्री दामोंदर (हजारीबाग) पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर) पांडे, श्री राम⁾सहाय, (राजनन्द गांव) पांडेय, डा० लक्ष्मीन रायण (मन्दसौर) पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर) पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली) पात्रोकाई हास्रीकिन, श्री (ब्राह्मम नीपुर) पाटिल', श्री ग्रान्तराव (खेड़) पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कं,परगांव) पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट) पास्टल, श्री कृष्णराव (जलगांव) पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद) पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया) पाणिप्रही, श्री चिन्तामणि (भृवनेश्वर)

पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री र जनलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री ग्रार० बालटण्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर) बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर) बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली) बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह, (भीलवाड़ा) बड़े, श्री ग्रार० व ० (खरगान) बरूग्रा, श्री वेदत्र (कालियाबोर) बर्मन, श्री ग्रार० एन० (बलूरवाट) बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर) बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार) वाजपेयी, श्री विद्याधर (ग्रमेटी) बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का) बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा) बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर) बालकृष्णन, (श्री के० (ग्रम्बलपुजा) बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति) बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग) बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (ग्रल्मोड़ा) वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़) बूटा सिंह, श्री (रोपड़)

बेरवा, श्री ग्रोंकार लाल (कोटा) बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक) ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़) ब्रह्मानन्द जो, श्री स्वामी (हमीरपुर) ब्राह्माण, श्री रतनलाल (डार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० ग्रार० (शाहबाद)
भहाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भहाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भहाचार्य, श्री दोनेन (सीरमपुर)
भहाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भगर श्री (झाब्ग्रा)
भागव, श्री वशेष्वर नाथ (ग्रजमेप्र)
भागवी, तनकपन श्रीमत (ग्रडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (ग्रमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मिलक, श्री मृख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मिल्लकार्जून, श्री (मेडक)
मियुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मरहोता, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)

महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा) महाजन, श्री वाई० एस० (वुलंडाना) महाजन, श्री विक्रम (कांगडा) महापात, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर) महाराज सिंह, श्री (मैन्युरी) महिषी, डा॰ सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर) मांझी, श्री भोला (जमुई) मांझी, श्री कुमार (क्योंझर) मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़) मारक, श्री के० (तुर) मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण) मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा) मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि) मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज) मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम) मायातेवर, श्री के० (डिडिगुल) मावलंकर, श्रींपी० जी० (ग्रहमदाबाद) मिधी, श्री नाथूराम (नागौर) मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद) मिश्र, श्री जीव एसव (छिदवाड़ा) मिश्र, श्री जगन्नाथ (मध्वनी). मिश्र, श्रो विभूति (मोतीहारी) मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय) मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज) मुकर्जी, श्री एचं० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व) मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा) मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा) मूर्ति, श्री बी० एस० (ग्रमालापुरम) मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोइ) ं मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण) मुहगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली) म्रम्, श्री योगेशचन्य (राजमहल)

मेलकोटे, डा॰ जी॰ एस॰ (हैदराबाद)
मेहता डा॰ जीवराज (ग्रमरेली)
मेहता, श्री पी॰ एम॰ (भावनगर)
मेहता, डा॰ महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम॰ (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श, श्री (मृशिदाबाद)
मोहम्मद यूसूफ़, श्री (प्रियाकुलम)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहस्मद शरीफ़, श्री (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदांगू)
यादव, श्री चन्द्रजीत (ग्राजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुराँमैया, श्री के० (गुन्टूर) रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी) रिव, श्री वयालार (चिरियकील)

राउत, श्री भोला (बगहा) राज बहादुर, श्री (भरतपुर) राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर) राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर) राजु, श्री पी० बी० जी० (विश्वखापत्तनम) राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़) राधाकृष्णन, श्री एस० (कुडलूर) रामकवार, श्री (टोंक) रामजी राम, श्री (भ्रकबरपुर) राम दयाल, श्री (बिजनौर) रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज) राम धन, श्री (लालकंज) राम प्रकाश, श्री (ग्रम्बाला) राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर) राम हेडाङ, श्री (रामटेक) रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा) राम सुरत प्रसाद, श्री (बासगांव) रामसेवक, चौधरी (जालान) राम स्वरूप, श्री (रावर्टसगंज) राम, श्री तुलमोहन (ग्ररारिया) राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया) राय, डा० सरदीश (बोलपुर) राय, श्रीमती माया (रायगंज) राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर) राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम) राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम) राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर) राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा) राव, श्री के० नारायण (बोबिली) राव, शी जगन्नाथ (छहपुर) राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री) राव, श्री पी० ग्रंकिनीडु प्रसाद (ग्रोंगोल)

राव, श्री जे॰ रामेश्वर (महबूबनगर) राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम) राव, डा० वी० के० ग्रार वर्दराज (वेल्लारी) राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा) रिछारिया, डा॰ गोविन्ददास (झांसी) रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी) रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा) रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद) रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा) रेड़ी, श्री के० कोदंडा रामी, (कुरनूल) रेड्डी, श्री पी० गंगा (ग्रादिलाबाद) रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर) रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्त्र) रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर) रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली) रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा) रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा) रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मन)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० ग्रार० (तिडिंवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर बिलयार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री श्रटलिबहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री श्रमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुद्कोटे)
वेकटस्वामी, श्री जी० (सिह्गेट)
वेकटासुञ्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (वीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिक्तोडी)
शंकर दयाल, सिंह (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैंदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री एवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री नवलिकशोर (दौसा)
शर्मा, श्री नाधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हिर प्रसाद (ग्रलवर)
शिश भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)

शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज) शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी) शास्त्री, श्री रामावतार (पटना) शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर) शास्त्री, श्री शिवकृमार (ग्रलीगढ़) शास्त्री, श्री शिवपूजन (विश्रमगंज) शाहनवाज खां, श्री (मेरठ) शिन्दे, श्री ग्रण्णासाहिब पी० (ग्रहमदनगर) शिनाय, श्री पी० ग्रार० (उदीपी) शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझनु) शिवण्या, श्री एन० (हसन) शुक्ल, श्री बी० ग्रार० (बहराइच) शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर) शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर) शेर सिंह, प्रो० (झज्जर) शैलानी, श्री चन्द (हाथरस) शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा
ग्रमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (ग्रमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना श्री (मिजोरम)

सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर) साठे, श्री वसन्त (ग्रकोला) साधुराम, श्री (फ़िलौर) सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक) सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचे ट्रिपलयम) साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल) सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा) सावित्री श्याम, श्रीमती (ग्रांवला) साहा, श्री ग्रजीत कुमार (विष्णुपुर) साहा, श्री गदाधर (वीरभूम) सिन्हा, श्री सीं एम (मयूरभंज) सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़) सिन्हा, श्री ग्रार० के० (फ़्रैजाबाद) सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (ग्रौरंगाबाद) सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर) सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर) सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपुर) सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर) सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा) सिधिया, श्री माधुवराव (गुना) सिंधिया, श्रीमती बी० श्रार० (भिड) सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट) सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर) सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि) सुद्रावलु, श्री (मयूरम) सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर) सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू) सेकरा, श्री इराज्मुद (मारमागोस्रा) सेझियान, श्री (कुम्बकोणम) सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड) सेठी, श्री ग्रर्जन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पिक्चम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री राबिन (ग्रासनसोल)
सेनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (शंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (ग्रानन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफ़न, श्री सी० एम० मुवन्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री ग्रार० वी० (मुदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

(₹)

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुजी)
हाजरा, श्री मनोरंजन (ग्रारामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (ग्रीसग्राम)
हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नुरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

ग्रध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा ग्राजाद श्री एच० के० एल० भगत श्री इससाक सम्भली श्री वसंत साठे श्री सी० एम० स्टीफ़न श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्याम लाल शक्धर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, स्रंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान स्रौर

प्रौद्योगिकी मंत्री

विदेश मंत्री

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्री

रक्षा गंत्री

नौवहन ग्रौर परिवहन मंत्री

विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्री

पैट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्री

उद्योग ग्रौर नागरिक पूर्ति मंत्री .

निर्माण श्रौर श्रावास तथा संसदीय कार्य मंत्री

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री

गृह मंत्री

संचार मंत्री

स्वास्थ्य भ्रौर परिवार नियोजन मंत्री

वित्त मंत्री

रेल मंत्री

श्रीमती इन्दिरा गांधी

श्री यशवन्तराव चव्हाण

श्री जगजीवन राम

श्री स्वर्ण सिंह

श्री उमाशंकर दीक्षित

श्री एच० ग्रार० गोखले

श्री के० डी० मालवीय

श्री टी० ए० पाई

श्री के० रघुरामैया

श्री राज बहादुर

श्री के० ब्रहमानन्द रेड्डी

डा० शंकर दयाल शर्मा

डा० कर्ण सिंह

श्री सी० सुब्रहमण्यम

श्री कमलापति विपाठी

मंत्रालयों/विभागों के प्राभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री

पूर्ति ग्रौर पुनर्वास मंत्री

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री

ऊर्जा मंत्री

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय

श्री स्नाई० के० गुजराल

श्री ग्रार० के० खाडिलकर

प्रो० नुरूल हसन

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

श्रम मंती इस्पात श्रौर खान मंती श्री रघुनाय रेड्डी श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंती
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंती
कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंती
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री
गृह मंत्रालय, कार्मिक और शासनिक सुधार विभाग
तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री के० ग्रार० गणेश श्री ए० सी० जार्ज श्री शाहनवाज खां महिषे डा० सरोजिनी श्री बी० पी० मौर्य

श्री स्रोम मेहता
श्री राम निवास मिर्धा
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी
श्री ए० पी० शर्मा
श्री स्रण्णासाहिब पी० शिन्दे
श्री विद्याचरण शुक्ल
श्री सुरेन्द्र पाल सिह
श्री एल० एम० तिवेदी

उप–मंत्री

उद्योग ग्रौर नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री स्वास्थ्य ग्रौर परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री पेंद्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री गृह मंत्रालय में उप-मंत्री

श्री जियाउर्रहमान ग्रंसारी
श्री वेदव्रत बरुग्रा
श्री बिपिनपाल दास
श्री ए० के० एम० इसहाक
श्री सी० पी० माझी
श्री एफ़० एस० मोहसिन

शिक्षा श्रौर समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति

विभाग में उप-मंत्री

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री

कृषि श्रौर सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री

संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री

इस्पात श्रौर खान मंत्रालय में उप-मंत्री

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री]

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री

निर्माण और भ्रावास मंत्रालय में उप-मंत्री

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री

सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्रालय में उप-मंती

पूर्ति श्रौर पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति

विभाग में उप-मंत्री

श्री भ्ररविन्द नेताम

श्री जगन्नाथ पहाड़िया

श्री प्रभुदास पटेल

श्री जे बी । पटनायक

श्री बी० शंकरानन्द

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद

श्री सुखदेव प्रसाद

श्रीमती सुशीला रोहतगी

श्री बूटा सिंह

श्री दलबीर सिंह

श्री केदार नाथ सिंह

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह

श्री धर्मवीर सिंह

श्री जी० वेंकटस्वामी

श्री बाल गोविन्द वर्मा

श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा वाद-विवाद (श्रिष्त ग्रन्दित संस्करण) LOK SABHA DEBATES (SUMMAR SED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा LOK SABHA

बुधवार, 6 ग्रगस्त, 1975/15 श्रावण, 1897 (शक)

Wednesday, August 6, 1975/Sravana 15, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

श्रध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए Mr. Speaker in the Chair

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के श्रधीन श्रधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुत्रार मुखर्जी): मैं केन्द्रीय उत्पाद णुल्क नियम, 1944 के प्रधीन जारी की गयी अधिमूचना संख्या सा० सां० नि० 908 (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 26 ज्लाई, 1975 के भारत के राजपत्न में प्रकाशित हई थी की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 9923/75]

कम्पनी स्रिधिनियम के स्रधीन स्रिधिसूचना तथा विलम्ब सम्बन्धी विवरण

विधि, न्याय आर कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुग्रा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

- (1) कम्पन ग्रिधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के ग्रन्तर्गत निम्नलिखित ग्रिधिसूचनाग्रों की एक एक प्रति:—
 - (एक) कम्पनी (लाभों का ग्रारक्षित निधि में ग्रन्तरण) नियम, 1975 जो दिनांक 26 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में ग्रधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 426 (ङ) में प्रकाशित रुए थे।

1284 LS-1.

- (दो) कम्पनी (ग्रारक्षित निधि से लाभांश की घोषणा) नियम, 1975 जो दिनांक 26 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्न में ग्रिधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 427 (ङ) में प्रकाशित हए थे।
- (2) उपर्युक्त ग्रिधिसूचनाग्रों के ग्रंग्रेजी संस्करणों के साथ उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9924/75]

भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (कब्जा) नियमों को सिक्किम राज्य पर लागू करने के बारे में ग्रधिसूचना

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): मैं भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी ग्रिधिनियम, 1933 की धारा 10 के ग्रन्तर्गत जारी की गयी ग्रिधिसूचना संख्या सां० ग्रा० 344 (ङ) (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 10 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ़ी (कब्जा) नियम, 1965 सिक्कम राज्य पर लागू किये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 9925/75]

कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1975 ग्रौर ग्रौद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1975

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्न सभा पटल पर रखता हूं :-

- (1) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि ग्रिधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के ग्रन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1975 (हिन्दी तथा श्रंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में ग्रिधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 871 में प्रकाशित हुई थी।
 - (दो) उपर्युक्त ग्रिधिसूचना को सभा पढल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 9926/75]
 - (2) श्रौद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (5) के श्रन्तर्गत श्रौद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1975 (हिन्दी तथा श्रग्नेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 26 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्न में श्रिधसूचना संख्या सा० सां० नि० 931 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी० 9927/75]

सभा की बैठकों से सदस्यों की श्रनुपस्थिति सम्बन्धी समिति Committee on absence of Members

कार्यवाही सारांश

श्री एस० एम० सिद्देया (चामराजनगर): मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की श्रनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 23 वीं बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की ग्रनुपस्थिति सम्बन्धी समिति Committee on absence of Members from the sittings of House

ग्रध्यक्ष महोदय: सभा की बैठकों से सदस्यों की श्रनुपस्थिति सम्बन्धी सिमिति ने श्रपने 22 वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में दी गई श्रवधि के लिये अनुपस्थिति की श्रनुमित प्रदान की जाये:--

- (1) श्री मोरार जी श्रार० देसाई
- (2) श्री एम॰ टी॰ राजू
- (3) श्री मधु दण्डवते
- (4) श्री पी० वी० जी० राज्
- (5) श्री विभूति मिश्र
- (6) श्री राम धन
- (7) श्री समर गुह
- (8) श्री श्यामनन्दन मिश्र
- (9) श्री नरेन्द्र सिंह
- (10) श्री नुहल हुडा

क्या सभा समिति की सिफारिश के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान करती है ?

ग्रनेक माननीय सदस्य : जें, हां !

ग्रध्यक्ष महोदय: ग्रनुमित प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

संसद सदस्यों के वेतन श्रीर भत्ते (संशोधन) विधेयक

Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill

निर्माण भौर भावास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया):श्रीमन मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्यों के वेतन भौर भत्ते अधिनियम 1954 का भौर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की भ्रनुमात दी जाये।

श्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"िक संसद् सदस्यों के वेतन श्रौर भत्ते श्रिधिनियम, 1954 का श्रौर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की श्रनुमित प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुन्ना ।

The motion was adopted

श्री के॰ रघुरामेया : श्रीमन मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं। श्रीमन मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।''

संसद सदस्यों के वेतन ग्रौर भत्ते सम्बन्धी समिति ने कई सिफारिशें की जैसे बिना किराये के 'ए' टाइप फलैट जिसमें नौकरों के लिये भी क्वार्टर हों, प्रति वर्ष 600 रूपये तक के बिजली पानी के बिल सरकार द्वारा चुकाये जायें । उन्हें सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जायें। 50 रुपए प्रति माह डाक टिकटों के खर्च के लिये दिये जाये। सदस्य को ग्रपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने हेतु परिवहन सुविधाएं दी जायं, वातानुकुलित डिब्बें की यात्रा, ग्रविवाहित, विधवा विधुर संसद् सदस्यों के परिवारों के लिये रेल पास की सुविधा तथा यही सुविधा संसद् सदस्यों के पति ग्रथवा पत्नी को उनके साथ काम में सहायता करने वाले स्टेनोग्राफ़रों इत्यादि को भी प्रदान की जाये। इनमें से कुछ सिफ़ारिशें पहले से ही कियान्वित करदी गई हैं स्रौर सरकार स्रन्य सिफ़ारिशों पर विचार कर रही है। हम यह महसूस करते हैं कि हमारे देश में संसद् सदस्यों को विश्व के ससद् सदस्यों की तुलना में सबसे कम आय और भत्ते प्राप्त है पर माननीय सदस्य वर्तमान आर्थिक स्थिति और सरकार की वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए उसकी मजबूरी को समझेंगे। सदस्यों के संतोषजनक रूप में कार्य न कर पाने और उनका सदन के भीतर और बाहर होने वाली कठिनाइयों को घ्यान में रखते हुए सर-कार ने उन्हें कुछ ग्रौर सुविधाय प्रदान करने का फ़ैसला किया है, ग्रिधिनियम की धारा 8 में ग्रावास सुविधाम्रों की व्यवस्था है लेकिन पानी, बिजली, निर्वाचन क्षेत्र म्रौर कार्यालय सुविधास्रों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं । इन सबका समिति द्वारा बनाय जाने वाले नियमों में किया जाना चाहिये था लेकिन उन्हे ऐसा करने में समर्थ बनाने के लिये अधिनियम में उपबन्ध होना चाहिये। अतः अधिनियम में संशोधन करके आवास तथा डाक सुविधायों के साथ यह शब्द पानी, बिजली, निर्वाचन क्षेत्र यौर कार्यालय सम्बन्धी सुविधायें भी जोडे जायेंगे।

कुछ सुविधायें उन्हें वास्तविक रूप में प्रदान की जायेंगी लेकिन कुछ अन्य सुविधाओं को उसी रूप में जुटा पाना सम्भव नहीं। उदाहरण के लिये निर्वाचन क्षेत्रों में याता सुविधाओं की व्यवस्था इत्यादि मामले पर समग्र रूप से विचार करने के बाद हमने सोचा कि इसे नियम समिति पर छोड़ना बेहतर है क्यों कि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत क्या दिया जाये इस बारे में वह सरकार से परामर्श अवश्य करेगी लेकिन इस कार्य के लिये समर्थ बनाने हेतु विधेयक में एक उपवन्ध होना चाहिये और यही इस विधेयक का उद्देश्य है।

ग्रध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुग्रा:

"कि संसद सदस्यों के वेतन ग्रौर भत्ते ग्रिधिनियम 1954 का ग्रौर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): सदस्यों का ग्रपने निर्वाचन-क्षेत्र से ग्राये मेहमानों की खातिर करने पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। उन्हें प्रतिदिन दो तीन रुपये डाक टिकटों पर खर्च करने पड़ते है। साथ ही टेलीफोन का भी काफी ज्यादा बिल ग्रदा करना पड़ता है। कई सदस्यों का ग्रंशकालिक टाइपिस्ट भी रखने पड़ते हैं। फलस्वरूप उनका बहुत खर्च होता है।

लेकिन सदस्यों का रियायतें प्रदान करने का यह उचित ग्रवसर नहीं है। यह बड़े दुःख की बात होगी यदि हमें इस ग्रापात स्थिति के दौरान जबिक देश में खर्च कम करने की बात की जा रही है, कुछ रियायत दी जायें। जब तक केन्द्रीय कर्मचारियों को उनकी महंगाई भत्ते की देय 6 किश्तों का भुगतान नहीं किया जाता तब तक हमें रियायतें न दी जायें। मंत्री महोदय हमें इत बात का ग्राश्वासन दें कि जब तक केन्द्रीय कर्मचारियों को उनकी महंगाई भत्ते की देय छह किश्तें नहीं दी जातीं तब तक सदस्यों का ग्रीर कोई सुविधायें प्रदान नहीं की जायेंगी।

Shri D. N. Tiwary '(Gopalganj): This Bill has been brought forward after considerable delay. The Committee had submitted its recommendations $2\frac{1}{2}$ years ago. There is great need for increasing the salaries and allowances of Members of Parliament as they are lowest paid legislators in the world.

The Committee has recommended that the Members should be provided with rent-free 'A' type flats, free postage stamps and he should be allowed to use Government jeeps for touring their constituencies. It is sad that the Hon'ble Minister has paid no heed to these recommendations.

As for secretarial service, we have suggested that there should be at least one stenographer for four M. Ps. But Government is giving us assistance in cash which is very insufficient. It would have been better if Government had provided this assistance in kind and not in cash.

The assistance of Rs. 500 being provided to us for various facilities is too meagre to meet our requirements. The proposed amendment will not help us get some more assistance. On the contrary people will censure us.

Government have not cut down their other expenditure but when the question of increasing the salaries and allowances of M.Ps. came, Government have started thinking in terms of effecting economy. It is very improper. Government should pay adequate salaries and allowances to M. Ps. so that they may carry on their Parliamentary work smoothly. The matter needs to be reviewed in its entirety and rules may be framed so as to provide more facilities to Members of Parliament.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon): The salaries of Members of Parliament are too less. They have to spend a lot on entertaining the guests from their consti-

[Shri R. S. Pandey]

tuencies. They have to maintain two establishments, one in Delhi and the other in their respective constituencies. They cannot manage all these heavy expenses within their limited selaries and allowances. If Government want M. Ps. to perform their duties efficiently, they should seriously think in terms of revising the salaries and allowances of M.Ps.

Government should also consider the question of granting pension to M. Ps. It is very essential. A Member who has worked for five years should get some pension so that he may maintain his dignity in the political life.

M. Ps. have to spend much on their correspondence with the people of their constituencies. Therefore, they should be paid some allowance for postage stamps. Members receive a large number of letters and they have to reply to these letters. Therefore, they should also be provided with some stenographic assistance.

We should be provided with facilities of steno, postage and sufficient allowance to meet electric and water charges.

श्री के० हनुमन्तैया (बंगलौर): वेतन ग्रौर भत्तों की वृद्धि के मामले में इस सभा में एकमत के बारे में कोई सन्देह नहीं है। सम्बद्ध समिति ने तथ्य तथा ग्रांकड़े एकत्र किये हैं।

मैं जब प्रशासन सुधार आयोग का सभापित था तब मुझे मंत्रिमंडल के सदस्य से अधिक वेतन मिलता था प्रत्येक बैठक के लिये 51 रुपए प्राप्त होते थे तथा टेलीफोन की सुविधा प्राप्त थी। मंत्री बनते ही ये सब सुविधाएं समाप्त हो गयी। 500-600 रुपये तो टेलीफोन बिल के ही देना पड़ते थे।

मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन की सुविधाएं दी जायें क्योंकि उन्हें अपने निर्वाचित क्षेत्र के पास सम्बन्ध बनाये रखना पड़ता है।

दूसरी ग्रोर पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है ग्रौर हमें संतुलित बजट रखना पड़ता है। मुझे पता चला है कि प्रत्येक सदस्य को बिजली ग्रादि की सुविधाग्रों के लिये 500 रुपये दिये जा रहें हैं। मेरा प्रस्ताव है कि सदस्यों मंत्रियों, ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 250 रुपये यात्रा भत्ता दिया जाये।

सदस्यों का वेतन बढ़ा कर इतना कर देना चाहिए कि यह 8000 रुपये वाषिक बन जाये। दैनिक भत्ते को 51 रु० से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया जाये।

हम सरकार से यह नहीं कहते कि वह संसद सदस्यों के प्रति उदार रवैया अपनाए अपितु यह आशा जरूर करते हैं कि वह उनके साथ न्याय करे। 15 वर्षों में महगाई बहुत बढ़ी है और हमने वृद्धि की मांग नहीं की है।

श्री श्रार० बी० स्वामीनाथन् (मदुरै): मैं भी सिफारिशें करने वाली समिति का सदस्य रहा हूं। समिति के सदस्यों का इस बारे में मतैक्य था कि सदस्यों को पेंशन दी जाये। कई देशों में तथा भारत की कई विधान सभाग्रों में भी सदस्यों को पेंशन मिल रही है। हम सभा के बहुत से सदस्य साधारण घरानों के हैं ग्रौर यदि उन्हें पेंशन नहीं दी जायेगी तो उन्हें भविष्य में ग्रपने परिवारों का पालन करना कठिन होगा। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी।

श्री मोरुन धारिया (पूना): इसमें सन्देह नहीं है कि हमारे देश में संसद सदस्यों को अपर्याप्त वेतन और भत्ते दिये जाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने संयुक्त सिमिति की निर्विवाद सिफारिशें यहां रखी हैं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश को अपने संसद सदस्यों की भलाई का ध्यान रखना चाहिए। सदस्यों की अन्य स्रोतों से आय को ध्यान में रखते हुए ऐसे सदस्य को अधिक वेतन भत्ते दिये जाने चाहिए ज़िनकी और आय नहीं है। विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में व्यय के आंकड़े 42,60,00 रुपये दिये गये हैं जोकि प्रति सदस्य प्रति मास 500 रूपये बैठते हैं। परन्तु जिस रूप में इसे रखा गया है, देश में वर्तमान वातावरण में उसका स्वागत नहीं होगा। मंत्री महोदय इस पहलू पर विचार करें अन्यथा इस प्रकार का कानून उनके विरुद्ध जा सकता है। लोक सभा, राज्य सभा सहित, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 5 किस्तों की अदायगी नहीं की जा सकी है मैं समझता हूं कि सदस्यों को पेंशन दी जानी चाहिए।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड): मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि जो कुछ सदस्यों को दिया जा रहा है वह बहुत कम है। यह संसद सदस्यों की न्यायोचित ग्रावश्यकताग्रों को भी पूरा नहीं करता। हम लोगों की स्थिति ग्रच्छी नहीं है ग्रौर जो सदस्य केवल इसी ग्राय पर निर्भर करते हैं ग्रर्थात् जिनकी ग्राय का कोई ग्रौर स्रोत नहीं है उनकी स्थिति तो ग्रौर भी बदतर है। रुपये का मूल्य बहुत गिर गया है। हमें 50 रुपए दैनिक भत्ते के स्थान पर ग्रब 150 रूपया दैनिक भत्ता दिया जाय।

सदस्यों को प्रतिदिन पांच लिटर पैट्रोल का भी एक कूपन दिया जाय। उन्हें ग्रंपने निर्वाचन क्षेत्र का भी काफी काम करना पड़ता है। ऐसे भत्ते के ग्रभाव में कार्य कर पाना ग्रसम्भव है। ग्राज संसद में कहा जाता है कि वस्तुग्रों के मूल्य गिरे ह परन्तु संसद भवन में रेलवे कैंटीन में ग्रभी हाल में मूल्य बढ़ाय गये हैं। लंच का मूय 4.20 से बढ़ाकर 6.30 कर दिया गया है।

तिमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश में सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। कम से कम उन सदस्यों को जिन्हों ने दो अवधियां पूरी करली है पेंशन दी जानी चाहिए।

कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो विधान सभाग्रों के सदस्यों को तो उपलब्ध हैं संसद सदस्यों को नहीं। केरल के सदस्यों को 150 रुपया पृथक से निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में दिया जाता है। संसद सदस्यों को कम से कम 500 रुपया निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में दिया जाये।

सदस्यों का निशुल्क टेले फोन कालों में भी वृद्धि की जाय। ट्रंक काल के लिये भी 100 रुपया ग्रथवा 200 रुपया भत्ता दिया जाये।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई मध्य-दक्षिण) : इस वि । यक के बारे में यह गलत फहमी निकाल देनी चाहिए कि जनता इसका विरोध करेगी । हम कोई गलत बात नहीं कर रहें हैं ।

वेतनों के मामले को नियम समिति ग्रंतिम रूप देगी । यह कार्य ग्रापात स्थिति के कारण किया जा रहा है । श्रथ्यक्ष महोइय : इस विधेयक पर बहुत पहले विचार हुग्रा था तथा इस बारे में सभी दलों में मतैवर था।

श्री एस० ए० कादर: जब कभी भी सदस्यों के वेतनों स्नादि का मामला उठाया जाता है तभी कोई न कोई विरोधी सदस्य इसका विरोध करता है। इसे हमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ भी नहीं जोड़ना चाहिए। 51 रुपए का दैनिक भत्ता वर्षों पूर्व निर्धारित किवा गया था। इसे 75 रुपये तह बढाया जाय।

संसद तथा विधान सभाग्रों के कई सदस्य ऐसे हैं जो सदस्यता के नाते मिलने वाली ग्राय पर पूर्णतः निर्भर हैं ग्रौर जब संसद तथा विधान सभाग्रों की ग्रविध समाप्त हो जाती है तो उनका गुजारा बहुत किठन हो जाता है। कर्मचारियों को उपदान मिलता है। ग्रन्य लोगों को पेंशन मिलती है पर संसद सदस्यों को जिन्होंने जनता की सेवा की है कुछ नहीं मिलता क्योंकि कानून ने उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की है। इस मामने पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। जहां तक यात्रा रियायत का सम्बन्ध है संसद सदस्य की पत्नी ग्रथवा पति को भी उसके समान पास दिये जायें। रेल मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए।

श्रध्यक्ष महोदय : ग्रमरीका, कनाडा ग्रौर जापान जैसे देशों में सदस्यों को बहुत ग्रधिक सुविधाएं मिलती हैं । हम उनकी ग्रर्थ-व्यवस्था से तुलना नहीं कर सकते । वहां प्रत्येक सदस्य को एक कमरा, दो स्टेनो तथा एक लाइब्रेरी तथा एक कार दी जाती है ।

भविष्य में स्टेनोग्राफरों, शिक्षकों ग्रादि के पद महिलाग्रों को उपलब्ध किये जायेंगे। इस बारे में हमें ग्रपना दृष्टिकोण बदलना होगा। पती को छोड़ कर महिलाग्रों में हमें माताग्रों, बहनों एवं पवियों का रूप देखना चाहिए।

ग्रनेक देशों में मंत्री, ग्रध्यक्ष तथा महा सचिव वकालत कर सकते हैं, क्योंकि वे पूर्णकालिक नहीं होते हैं। उन्हें ग्रल्पकालिक सेवा के लिए पूर्णकालिक सेवा की तुलना में ग्रधिक वेतन मिलता है। मैं नहीं समझता कि यह प्रथा इस देश में सम्भव है।

वहां जलपान गृह भी ग्राधुनिक ढंग के हैं । सभी विधान मण्डलों के जलपान गृहों को सहायता मिलती है ग्रौर वहां ग्रतःधिक सस्ता ग्रौर पौष्टिक भोजन मिलता है ।

विदेशी शिष्ट मण्डलों को श्रत्यधिक भत्ता मिलता है। लेकिन भारतीय शिष्ट भंडल को भत्ता बहुत कम मिलता है ग्रौर उन्हें ग्रपने खान-पान पर उससे बहुत ग्रधिक व्यय करना पड़ता है। ग्राप को वहां दूसरे विदेशियों के समान ही व्यय करना पड़ता है।

ग्रापको जो वेतन मिलता है वह कई विधान सभा के विधायकों को मिलने वाले वेतन के बराबर ही मिलता है। ये वेतन लगभग 20 वर्ष पूर्व निर्धारित किये गये थे।

यहां दैनिक भत्ता ग्रीर याता भत्ता भी यहां के कई विश्वविद्यालयों से बहुत कम है। यहां के शिष्ट मण्डलों के प्रतिनिधियों को विदेशी मुद्रा 50 पींड से ग्रधिक नहीं मिलती है। ले िन वर्तमान परिस्थिति में हमें जो कुछ मिल रहा है हम उसी से सन्तुष्ट हैं। फिर भी इन सभी पहलुओ पर विचार करना होगा और उन्हें सुसंगत बनाना है। तथा यह कार्य आगामी समिति के एठन हुने पर ही किया जाना चाहिए।

श्री के॰ रघुरामैया: जैसा कि मैंने ग्रारम्भ में कहा है कि इस वृद्धि से सदस्यों की सभी ग्रावश्यकताए पूरी हो जायेंगी ऐसा सरकार ने नहीं सोचा है। वस्तुतः हमने समिति की सिफारिशों की जांच करने के बाद यह ग्रमुभव किया है कि इस समय कुछ सिफारिशों को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस पर दा मत हैं। एक यह कि इस पर जनता की क्या प्रतिकिया होगी। दूसरे सदस्यों को इतना वेतन व भत्ता ग्रवश्य मिलेना चाि ए जिससे वे ग्रपने कर्तव्यों का सन्तोषजनक तथा कुशलतापूर्वक निवंहन कर सकें। ग्रतः सरकार को बीच का मार्ग ढू ढ़ना पड़ेगा। सरकार को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखना होगा ग्रौर वर्तमान स्थित को भी ध्यान में रखना होगा। जब कि हम प्रत्येक व्यक्ति से यह ग्रनुराध कर रहे हैं कि वे ग्रपनी मजूरी न बढ़ायें। ग्रतः इस संदर्भ में तथा संसद सदस्यों का ग्रपना कर्तव्य का समुचित रूप से पालन करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कियें गये हैं ग्रौर उन्हें स्वीकृत किया जाना चाहिए।

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"िक संसद सदस्यों के वेतन ग्रौर भत्ते ग्रिधिनियम, 1954 का ग्रौर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा।

The motion was adopted

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रब हम विधेयक परखण्डवार विचार करेंगे । श्री रामावतार शास्त्रो ने एक संशोधन क, सूचना दी है । क्या वह उसे पेश करेंगे ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): जी हा । मैं ग्रपना संशोधन संख्या 1 पेश करता हूं।

Sir, the Joint Committee has recommended some more facilities and on the basis of these recommendations this Bill has been brought forward. A provision has been made in this Bill to pay cash in lieu of all or any facilities proposed to be given to the Members of Parliament. But it is a departure from the recommendations of the Joint Committee because they have recommended that the facilities should be given in kind rather than in cash. If the facilities are given in cash the purpose of this Bill would be defeated. The Committee has never intended to pay cash in lieu of all those facilities. If there is any difficulty in the way of the members to discharge their duty in their constituencies, cash amount can be given for any particular item, but not for all.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किया गया संशोधन स्वेकृत किया जाना चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों से ग्राने वाले सदस्यों के लिए वाहन ग्रादि की व्यवस्था करना ग्रानिवार्य हो जाता है । इसके लिए नकद राशि देने से कार्य सिद्ध नहीं होगा । ग्रापने एक मुक्त [श्र. भोगेन्द्र झा]

राशि देने का प्रस्ताव किया है। लेकिन बहुधा यह राशि दूसरे कार्यों पर खर्च की जायेगी स्रौर उद्देश्य की सिद्धि भी नहीं होगी यह तो लोगों के साथ धोखा करने वाली बात होगी।

श्री के० रघुरामैया: साधारण कारणवश यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जी सकता है, क्योंकि मैंने ग्रारम्भ में ही संकेत किया है कि कुछ मामलो में सुविधाएं ग्रन्य रूप में नहीं दी जा सकती ग्रंथीत सभी सदस्यों विधायकों के लिए जीप ग्रादि की व्यवस्था नहीं होगी। इस लिए नकद राशि देना उचित समझा गया है।

ग्रथ्यक्ष महोदय : द्वारा श्री रामावतार शास्त्री का संशोधन संख्या-1 मतदान के लिए रखा गया तथा ग्रस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

ग्रध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का ग्रंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुन्ना ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया । Clause 2 was added to the Bill.

खं•ड-3

श्री राम हेडाऊ : (रामटेक) : मैं ग्रपने संशोधन संख्या 2 ग्रीर 4 प्रस्तुत करता हूं। श्री रामावतार शास्त्री : मैं ग्रपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Ram Hedaoo: The facilities being given to members of Parliament in their constituencies are important because they have to work there. They have to keen close contact with their constituents. If the facility of free travel in State Transport buses is given to them their job can become easier. You will find how Government jeeps are misused by Government Officials. I think it should not be very difficult for Government to provide members of Parliament with Government jeeps so that they may visit their constituencies in vast rural areas. Therefore a provision should be made in this Bill that a member of Parliament may be provided with a Government jeep. Whenever it is required by him.

When one ceases to be a member of State Legislature or Parliament his condition becomes miserable because there is no provision of posion for him.

Therefore a provision should also be made in the Bill to grant pension to a Member of Parliament even if he remains an M. P. for only one term.

श्राध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ श्रीर 4 मतदान के लिए रखे गये तथा ग्रस्वीकृत हुए ।
The amendments were put and negatived.

श्रध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा श्रस्वोकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

्म्रध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है "कि खण्ड 3 विधेयक का ग्रग् बने" प्रस्ताव स्वीकृत हुन्ना (The motion was adopted.)

> बण्ड 3 विधेयक में जोड दिया गया। Clause 3 was added to the Bill.

श्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 1, श्रिधिनियमन सूत्र श्रीर विधेयक का नाम विधेयक का श्रंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुम्रा । The motion was adopted.

खण्ड 1, ग्रजिनियम सूत्र ग्रोर विशेषक को नाम विशेषक में जोड़ दिए गये। Clause 1, the enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

श्री के॰ रबुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"िक विधेयक पास किया जाये"।

(Pali): The committee should C. Daga seriously the suggestions put forward by the Members in regard to this Bill. with The members have to keep close contact the constituencies. It is a guestion of his dignity and in order to enable him to serve his constituency more efficiently and work for the betterment of the people of his constituency he should be given every possible facility to fulfil his responsibility towards his constituents as are being given to the high officers serving in the Government.

Br. Kailas (Bombay-South): This is not a comprehensive Bill and even then the hon. Minister has stated about the adverse financial position. Here it is not a question of funds but that of the dignity of a member of Parliament. Therefore the question of funds should not be raised regarding facilities to be given to members of Parliament. Members of Parliament should be given facilities so that they may be able to think that they represent not only their constituencies but the whole of the country, and make their contribution towards the people and the development of the country with greater efficiency.

A member when he comes to Delhi to atend a session has to give up his profession and he has to depend only on his salary and allowances as a member of Parliament.

We do not required cash money. We required facilities in kind.

[Dr. Kailas]

The member who remains in the house for one term should get pension at the rate of 33 per cent, for two terms 50 per cent and for 3 terms 75 per cent.

The wife of an M.P. should get a 1st class railway pass for full terms of five years just like the M.P.

श्री वसन्त साठे (ग्रकोला) : मंत्री महोदय को इस विधेयक के लाने पर धन्यवाद । संसद सदस्यों को बहुत काम करना होता है । उन्हें दी जाने वाली ग्रतिरिक्त राशि के लिए के पैसे का रोना नहीं रोना चाहिए, क्योंकि उन्हें जितना रुपया दिया जाएगा उससे दस गुना ग्रधिक तस्करी को रोक कर ही बचाया जा सकता है ।

श्रन्य देशों में संसद सद यों की सहायता के लिए स्नातकोत्तर छात्रों की सेवाएं ली जाती हैं। कुछ जेब 'वर्च देकर उनकी सेवाएं यहां भी ली जा सकती हैं। यहां भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे सदस्य श्रपना कार्य ग्रधिक कुशलता श्रीर ग्रासानी से कर सकते हैं।

आज एक बैंक के चपरासी को भी 800 रुपये मिलते हैं । क्या हम लोग उनसे भी गये बीते हैं। ।तः इस विधेयक के सम्बन्ध में धनाभाव का बहाना बड़ा ही लचर और स्राधारह न है।

श्रध्यक्ष महादय: श्रापको अब जो मिल रहा है उसी पर सन्तोष करें श्रौर इन्तजार करें उस उपयुगत समय का जब कुछ श्रौर पा सकें। अब मैं विधेयक को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"िक विधेयक पास किया जाए"।

अस्ताव स्वीकृत हुआ। The motion was adopted.

स्तेमः शुक्त टेरिफ विवेयक CUSTOMS TARIFF BILL

विस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"िक सीमा शुल्क सम्बन्धी विधि का समेकन ग्रौर संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए"

ास विधेयक का मुख्य उद्देश्य ग्रायात सीमा शुल्क टैरिफ की नामावली को युक्तिसंगत तथा ग्राधुनिक बनाना है। वर्तमान टैरिफ ग्रिधिनियम का ग्रायात टैरिफ कार्यक्रम वर्तमान स्थिति में पुराना पड़ गया है।

टैरिफ संशोधन समिति ने सिफारिश की थी कि आयात टैरिफ कार्यक्रम का संशोधन किया जाये और इसे बुसेन्ज टैरिक ना गवल के अनुसार भारत की व्यापातक प्रणाल का ध्यान में रखते हुए बनाया जाये। इस समिति ने वर्तमान टैरिफ अधिनियम तथा निर्यात टैरिफ कार्यक्रम के आवधानों के बारे में भी सुझाव दिये थे और सिफारिश की थी कि भारतीय टैरिफ (संशोधन)

अधिनियम 1949 को एक पृथक कानून के रूप में न रखा जाये और इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को, यदि आवश्यक हो तो, संशोधित टैरिफ अधिनियम में ही शामिल किया जाये।

मरकार ने टैरिफ संशोधन समिति की सिफारिशो को स्वीकार कर लिया था। 24 दिसम्बर, 1969 को इस हेतु लोक सभा में सीमाशुल्क टैरिफ विधेयक 1969 पेश किया गया जिसे प्रवर समिति को भेजा गया। लेकिन प्रवर समिति की रिगोर्ट पेश होने से पहले चौथी लोक सभा भंग हो गयी। ग्रत: इस विधेयक को लाया जा रहा है।

इस विधेयक की मुख्य बातें यह हैं कि ग्रायात टैरिफ कार्यक्रम में वस्तुग्रों की व्याख्या कुसेल्ज टैरिफ नामावली के ग्राधार पर थी लेकिन नामावली का प्रत्येक शीर्षक भारत के ग्रायात व्यापार के ही ग्रनुसार था। इन उप-शीर्षकों का मुख्य उद्देश्य ग्रायात शुल्क में मिन्न दरां के लिये व्यवस्था करना, ग्रायात व्यापार के महत्व की प्रत्येक वस्तु का उल्लेख करना ग्राथवा संरक्षण त्मक शुल्क की वस्तुग्रों को पृथक पृथक दिखाना है। ग्रायात टैरिफ कार्यक्रम में शुल्क दरें निर्धारित करते समय वर्तमान दर हांचे को कायम रखने का प्रयास किया गया है।

विधेयक के खण्ड 1(3) में यह बात स्पष्ट है कि इसे तुरन्त लागू नहीं किया जायेगा विल्क उस तिथि से किया जायेगा जिसे भारत सरकार ग्रिधसूचना द्वारा निश्चित करे। ग्रतः वर्तमान टैरिफ इस विधेयक के ग्रिधिनियम बनाने के बाद भी जारी रहेगा। ग्रतः विधेयक के पास होने के छः महीने बाद नया ग्रायात टैरिफ लागू किये जाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि इस ग्रविध के दौरान इस हेतु तैयारी की जा सके।

स्रध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्ना कि सोमा-शुल्क सम्बन्धी विधि का समेकन स्रौर संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए"।

Shri Ishaque Sambhali (Amroha): This Bill is quite good but it does not specify what concession has been given to those commodities which are required for medical treatment such as X-ray films and such other things?

Importers in India have earned huge profits in recent years and their profit has to be slashed down. With this view it is not wrong to raise the tariff rates. But there is evasion of customs duty on a very large scale in the country and it will be better to make provision in this Bill to plug to the loopholes through which customs duty is being evaded.

There is good deal of scope to check corruption in the Customs Department. There can be no objection to enhancing the tariff rates but the revenue must be fully realised. It is possible only when corruption is rooted out from the Customs Department. To achieve that end, a complete overhauling of the Customs Department should be undertaken or a special vigilance department be created to keep a close watch on the working of this Department. This Bill will serve no purpose until steps are taken to root out corruption from this Department.

[Shri Ishaque Sambhali]

I will certainly say one thing that the tariff rates on purely luxury goods should be increased but the tariff on the commodities or equipments required for medical purposes and hospitals should not only be reduced but it should be completely exempted. It will help the common man.

A study team visited several countries of the world to study machinery for realisation of customs duties there. The team made certain recommendations. But they are still lying in cold storage and no action has been taken to implement them. Minister should pay attention towards that.

उपाध्यक्ष महोदय पोठासीन हुए।

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

I am looking forward to the day when the corrupt big custom officials who are rolling in wealth will be trapped and held under DIR and MISA. With these words I support the Bill.

श्री श्ररविन्द बाल पजनौर (पांडेचेरी) : मैं इस विधान का समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय इसे सही समय पर सदन के समक्ष लाए हैं इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। यह एक ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है लेकिन लगता है कि कुछ सदस्यों ने इसे ग्रच्छी तरह पढ़ा नहीं है ग्रीर इसीलिये वह इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। यह विधेयक स्वदेशी उद्योगों तथा स्व-देशी उत्पादों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके स्रतिरिक्त इस विधेयक से तस्करों की गतिविधिया पर रोक लगाने तथा काले धन के प्रसार को कम करने में सहायता मिलेगी। ग्रापातकालीन स्थिति में इस विधेयक को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विधेयक द्वारा भारी प्रशुल्क लगाया गया है ताकि देश में कुछ वस्तुस्रों का स्रायात न किया जाए ग्रौर देश में इन वस्तुग्रां के उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन मिले। यदि सरकार तस्करों की गतिविधियां को रोक सके तो तस्करी की वस्तुए बाजार में नही बिकेंगी। हम लोग स्वय जनता को इन वस्तुम्रां को खरीदने का प्रलोभन देते हैं। कुछ मंत्रियों या बड़े म्रधिकारियों के दफ्तरों में भ्राप जाएं तो भ्रनेक विदेशी वस्तुएं देखने को मिलेंगी। इससे वहां जाने वाले लोगा के मन में भी वैसी वस्तुत्रों को प्राप्त करने का प्रलोभन होता है। य्रत: मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह इन बिदेशी वस्तुओं के बारे में पूछ-ताछ करें। मैं यह नहीं कह रहा कि इनको जब्त किया जाए। यदि वह व्यक्ति जिनके पास विदेशी वस्तुए हैं उनका लेखा-जोखा देने में ग्रसमर्थ है तो उन वस्तुग्रां पर भी भारी प्रशुल्क लगाया जाए।

कुछ वस्तुग्रां के मामले में उचित रियायत नहीं दी जा रही। हमारे देश में उन् वस्तुग्रां में प्रतिस्पर्धा नहीं है जिनको तैयार करने में दक्षता की ग्रावश्यकता होती है। प्रतिस्पर्धा के ग्रभाव में इन वस्तुग्रों के निर्माता ग्रपने एकाधिकार का ग्रनुचित लाभ उठाते हैं। उनकी किस्म में सुधार करने के प्रति कोई रुचि नहीं लेते ग्रौर ऐसी ग्रवस्था में ग्रगर हम विदेशी वस्तुग्रां को देश की मंडी में ग्राने का ग्रनुमित नहीं देते तो इससे उन लोगा को ग्रनावश्यक संरक्षण मिलेगा। इसलिए थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा का होना ग्रावश्यक है।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और मैं ग्राशा करता हूं कि ग्रगले सब में छोटे मोटे मामलीं पर पूर्ववत विधेयक लाने के स्थान पर ऐसे ही विधेयक लाए जाएंगे। मंत्री महोदय का कहना है कि यह विधेयक एक नियत तिथि से लागू किया जाएगा। ग्रापने कुछ बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है पर उनकी सम्पत्ति के बारे में क्या किया गया है। मेरे राज्य में ग्रोर उसके पडौसो राज्यों में उनकी सम्पत्ति के बारे में कुछ नहीं किया गया।

किझाकरई ग्रौर ग्रहरा पट्टनम में कुछ लोगों ने 50 लाख, 70 लाख या एक करोड़ रुपया तक लगा कर मकान बनाए लेकिन वह उनमें रहते नहीं हैं उन्होंने केवल उनकी रखवाली के लिये एक चौकीदार रखा हुग्रा है। इस ग्रापातकालीन स्थिति में सरकार का इस संबंध, में क्या कार्यवाही करने का विचार है।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे जिसमें अमीर श्रौर गरीब के बीच के अन्तर को कम किया जाएगा लेकिन इन लोगा का एक काला बैंक है ग्राप चोहें जो उपाय करें वह किसी न किसी ढंग से गैसा इस देश में ले ग्राएगे। कानून के ग्रनुसार विदेशों से धन केवल रिजर्व बैंक द्वारा ही ग्रा सहता है लेकिन इन काले बैंक वालों की एक पृथक प्रणाली है। यह धन को किसी एजेंसी द्वारा भेजते हैं ग्रौर बिना किसी बाधा के ग्रपना काम चलाते हैं। इसका कारण यह है कि सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारी वर्तमान कानून को उचित ढंग से लागू नहीं कर रहे। जब भी लोग विदेशां से त्राते हैं तो वह ग्रपने साथ कुछ विदेशी वस्तुएं लाते हैं लेकिन सीमा-शुल्क ग्रधिकारी केवल उन्हीं गरीब लोगों को जो इक्का दुक्का चीज लाते है तग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई दो पैन लाया है तो उससे वह एक मांगते हैं और अगर कोई दो घडियां लाया है तो वह कहते हैं कि एक हमको दे दो। लेकिन वास्तविक तस्करों को वह कुछ नहीं कहते क्यां कि वह सीमा-शुल्क ग्रधिकारियों को रिश्वत देते हैं। ग्राप सीमा-शुल्क ग्रधिकारियों के घर में जाए तो ग्राप को वहां ग्रनेक विदेशी वस्तुएं मिलेंगी। संबधित ग्रीधकारी इस बारे में ग्रावश्यक नियंत्रण नहीं रखते इन लोगों पर निगरानी रखनी चाहिए और केवल ईमानदार लोगों को सीमा-शुल्क विभाग में रखना चाहिए । साथ ही इन लोगों को एक स्थान पर एक वर्ष से प्रधिक नहीं रखना चाहिए। सारा दोष हमारे प्रशासन का है। हम चाहें जो विधान बना लें जब तक वह उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किए जाते उनसे कुछ लाभ नहीं होगा। यह क्रियान्वयन हमारे द्वारा इन 15-20 वर्षो में प्राप्त किए गए अनुभव पर आधारित होना चाहिए।

ग्राजादी के बाद ग्रपने उद्यमियों को देश में वस्तुएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करने, ग्रार्थव्यवस्था को संतुलित करने तथा रिजर्व बैंक को उचित रूप में रखने के लिए हमने विदेशी वस्तुग्रों को विनियमित करना शुरू किया ग्रीर इस प्रकार के कई कातून पेश किए। जब हम विधान पर इस दृष्टि से विचार करें तो हमें ग्रपने पिछले 15 वर्ष के ग्रनुभव को ध्यान में रखना होगा। यदि ऐसे विधान में संयुक्त समिति द्वारा एक पैराग्राफ में यह बताया जाए कि यह हमारा पिछला ग्रनुभव है ग्रीर ऐसा हो रहा है तो हमारे लिए उस विधान को समझने में मठिनाई हो रही है तो ग्राम जनता ग्रयवा ग्रधिकारी इसे किस प्रकार समझ सकते हैं। ग्रापको संक्षेप में बताना चाहिये कि पहला विधेयक दूसरे विधेयक से किन बातों में भिन्न है तभी हम इसे ग्रच्छी तरह समझ संकेंगे ग्रीर ग्रपने विचार सही रूप में प्रकट कर पाएंगे।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी: मैं उन सदस्यों का ग्राभारी हूं जिन्होंने कि सीमा-शुल्क टैरिफ विधेयक पर ग्रपने विचार प्रकट किए हैं। यह विधेयक न तो सीमा-शुल्क प्रशासन के

[श्रां प्रणब कुमार मुखर्जी]

लिए ग्रीर न ही देश में हो रही तस्करी तथा ग्रन्य प्रकार के ग्राधिक ग्रपराधा को रोकने के लिए लावा गया है। यह विधेयक ब्रुसेल्ज नामावली को वर्तमान टैरिक की वस्तुग्र पर वर्तमान दरों को कायम रखते हुए लागू करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। हम तो केवल परम्परागत नामावली का पारवर्तित करके इसे ब्रुसेल्ज टैरिफ नामावल के ग्रनुसार कर रहे हैं जोकि ग्राजकल ग्रंतरिष्ट्रीय मानक है।

मैं माननीय सदस्य श्री पजनौर की इस बात से हसमत हूं कि यह एक ग्रत्यंत तकनीकी विधेयक है इसीलिए जब 1969 में इस विधेयक को पुरस्थापित किया गया ग्रीर इसे प्रवर समिति को भेजा गया था, लेकिन लोक सभा के विघटित हो जाने के काण प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन में नहीं रखा जा सका। वर्तमान लोक सभा में इसे पुनः पुरस्थापित किया गया ग्रीर इसे फिर प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति ने विभिन्न शहरों का दौरा किया ग्रीर लोगों के मौखिक बयान लिए तथा व्यापार ग्रीर उद्योग द्वारा दिए गए विभिन्न ज्ञापना की जांच भी की है। मेरा यह भी निवेदन है कि परम्परागत नामावली को बुसेल्ज टैरिफ नामावली में परिवर्तन करने से व्यापार तथा उद्योग के लिए ग्रमुविधा पैदा होगी ग्रतः प्रश्न केवल लोगों को इन वातों को समझाने योग्य बनाने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने का ही नहीं ग्रपितु नई परिस्थितियों में व्यापार तथा उद्योग को भी नई नामावली से ग्रवगत करने का भी है।

इस परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए हमने छः महीने का समय देने की व्यवस्था की है। तस्करी विरोधी तथा अन्य कार्यवाहियों के बारे में भी चर्चा को गई है। तस्करों के विका क्या उपाय किए जा रहे हैं इसके बारे में मैं सदस्यों को विस्तार से बता चुका हूं। मैं उनको पुनरावृति नहीं करना चाहता विशेषकर जबकि वह इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। श्री इसहाक संभली ने नौकाम्रां के बारे में विशेष रूप से पूछा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि समुद्र तट पर निगरानी रखने के लिए रखी गई 20 नौकाम्रों में से 19 नौकाएं काम कर रही हैं। यह हो सकता है कि ये नौकाएं काम करते करते कभी खराब भी हो सकती हैं, कभी उन्हें छोटा मोटी मरम्मत के लिए वर्कशाप भेजना पड़ता है। अतः यह कहना ठीक नहीं कि नौकाएं शुरू से काम नहीं कर रही।

हमने विभिन्न श्रेणियों के लगभग 500 ग्रधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि बहुत कम लोग गिरफ्तार किए गए हैं यह सच नहीं है। नए ग्रधिनियम के ग्रंतर्गत 1300 से ग्रधिक लोगों की गिरफ्तारी के लिए ग्रादेश दिये गए हैं ग्रौर यह सिल हिला जारो है। यह कहना सही नहीं है कि केवल ग्रापातकालीन स्थिति में ही यह गिरफ्तारियां की जा रही है। पिछले सप्ताह मैंने सितम्बर 1974 से जुलाई 1975 तक को ग्रविध में मारे गए छापों तथा गिरफ्तार किए गए तस्करों ग्रौर फरार हूए तस्करों तथा उनकी सम्पति को कुर्क वरने के बारे में जारी किए गए नोटिसों का ब्यौरा दिया था। इन ग्रांकड़ो में कुछ ग्रंतर हो सकता है लेकिन इसका ग्रर्थ यह नहीं है कि हमारे प्रयासों में कुछ कमी ग्राई है।

तस्कर विरोधी ग्रभियान जारी है । इस के लिए सदन ने हमें भारत रक्षा नियम ग्रांसुका ग्रादि द्वारा ग्रधिकार प्रदान किए हैं ग्रौर उनका उपयोग यथोचित समय पर किया जा रहा है।

जहां तक सुरक्षणात्मक टैरिफ का संबंध है हम ने जहां तक संभव हो सका वर्तमान टैरिफ दर को कायम रखा है । लेकिन कुछ मामलों में वित्त विधेयक ग्रथवा टैरिफ संशोधन के कारण हम इस के ग्रनुसार न चल सके ग्रीर उन्हें लागू करने के लिए हमें विधेयक में कुछ परिवर्तन करने पड़े । मैं ग्राशा करता हूं सदन एक मत से इस विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करेगा। उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"िक सीमा-शुल्क सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुन्ना । The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"िक खण्ड 2 से 13, प्रथम अनुसूची, दितीय अनुसूची, खण्ड 1, अधिनिय न सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा । The motion was adopted

खण्ड 2 से 13 प्रथम भ्रनुसूची, द्वितीय भ्रनुसूची खण्ड 1, भ्रधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 2 to 3, the First Schedule, the Second Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सीमा-शुल्क विधि का समेकन भ्रौर संशोधन करने वाले विधेयक को, प्रवर सिमिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित किया जाए।"

Shri Ishaque Sambhali (Amroha): It is a matter of gratification that the hon. Minister has assured the House that he will keep in mind the suggestions given to him. We do want that the Government should earn revenue on imported goods.

I with the hon. Minister were to look into the working of customs department. The customs authority did not spare from levy of custom duty even the tanks which were seized and brought by our Jawans as war bounty during the Indo-Pakistan war. The Defence Ministry had to fight hard to get such tanks exempted from customs duty. I therefore want that the department should be toned up and rationalised.

श्री डी॰ डी॰ देसाई (कैरा): संयुक्त सिमित ने ग्रायात तथा निर्यात करने वाले देशों की सुविधा के लिये टैरिफ नामावली पर विचार किया था। लेकिन सीमा-शुल्क ग्रिधकारी संभवतः नामावली की सही ग्रयवा तुरंत परिभाषा न कर सके हों। हमें माल ले जाने के लिये समय ग्रविध निश्चित करनी चाहिये। कोई भी वस्तु हो, उसे 4 से 6 दिन तक से ग्रिधक नहीं रोका जाना चाहिये। यदि जांच का उद्देश्य नामावली की स्पष्ट व्याख्या ही हो तो उस मामले में शुल्क दर विलम्ब का कारण नहीं होना चाहिये।

[श्रें डो॰ डो॰ देताई]

नये उत्पादों की नित्यप्रति वृद्धि से लगातार श्रेणियों को जोड़ने ग्रथवा परिवर्तन करने की ग्रावश्यकता पड़ेगी ग्रीर शुल्क निश्चित करने होंगे। चूंकि उत्पाद का उपयोग शुल्कदर निर्धारित करने के लिये निर्णयक होगा। ग्रतः इसके "उपयोग" को ही शुल्क दर निर्धारण के लिये ग्राधार माना जाये। ग्रतः प्रशिक्षण तकनिकी पहुनु तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये बल्कि सीमा-शुल्क टैरिफ, ग्रिधिनियम, 1975 तथा इसके कार्यक्रम तक, ही रहना चवहिये ग्रौर सम्बन्धित व्यक्ति के ग्रदर शीघ्र काम करने की भावना पैदा की जानी चाहिये ताकि देश को ग्रायात तथा निर्यात व्यापार को क्षति न पहुचे।

विभाग को माल ले जाने सम्बन्धी समय ग्रविध निश्चित करने के बारे में निदेश जारी किये जाने चाहियें।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह): मैं ग्रभरक उद्योग से सम्बन्ध रखता हूं। ग्रवभूल्यन ग्रविध के बाद, ग्रभरक के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाया गया। इसके फलस्वरूप नेपाल को 5 करोड़ रुपये की लागत के ग्रभरक की तस्करी हुई। ग्रत: ग्रभरक के विभिन्न किस्मों पर शुल्क में 20 प्रतिशत की कमी करनी पड़ी। ग्रब ग्रभरक पर उत्पाद शुल्क भी लागू है।

यदि ग्रभरक पर उत्पाद शुल्क लगाया जाये तो इसका ग्रर्थ कर को दो गुणा करना है। छोटे व्यापारियों के लिये इस से कठिनाईंगा पैदा हो जायेंगी। जब हम ग्रपनी निर्यात तथा ग्रायात प्रक्रिमाग्रों को सरल बना रहे हैं तो इस श्रम प्रधान उद्योग पर इस प्रकार के दुगने कर लगने के फलस्वरूप ग्रधिक से ग्रधिक कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी।

ग्रभरक उद्योग को व्यवहार्य तथा समृद्ध बनाने के लिए ग्रभरक के निर्यात शुल्क पर हमें कुछ राहत देनो चाहिये। इस दुगने कर की ग्रोर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा इसे यथाशीझ हटा दिया जाना चाहिये।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी: माननीय सदस्यों ने कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये हैं और प्रशासनिक मशीनरी को सुधारने के लिये कहा गया है । सुधार की काफी गुंजायश है और इस विशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है ।

जब कभी भी ग्रावश्यक होगा प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग में की जायेगी ताकि कार्य तीव्रगति से हो ग्रौर कोई भी सामग्री ग्रतुचित ढग से रुके नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"िक सीमा-शुल्क सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रवर समिति द्वारा प्रतिबेदित रूप में पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुन्ना । The motion was adopted

विश्वविद्यालय ग्रान्दान ग्रायोग के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव MOTION RE: ANNUAL REPORT OF THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR 1972-73

शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन): मैं प्रस्ताव करता है:

" कि यह सभा विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन जो 9 दिसम्बर, 1974 को सभा पटल पर रखा गया था, पर विचार करती है।"

सरकार ने विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न सुधार करने का प्रयत्न किया था लेकिन कुछ लोगों के गुटों ने विश्वविद्यालयों में गडबड़ी फैलाने का निर्णय किया। शिक्षा के लिये आवश्यक शांतिमय वातावरण बनाने के बजाय उन्होंने हिंसा, डर ग्रौर दबाव का वातावरण बनाया। यह बड़े ही संतोष की बात है कि ग्रापात स्थिति के कारण उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने जो डर था वह समाप्त हो गया है ग्रौर ग्रब विश्वविद्यालयों में सामान्य रूप में शांति से काम हो रहा है।

विश्वविद्यालय शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या छातों और कालिजों की बढ़ती हुई संख्या है। यह देश के संसाधनों की सोमा से बाहर है और इससे बेरोजगारी ही नहीं बढ़ रही है बल्क उनकी संख्या भी बढ़ रही है जिन्हें कोई काम नहीं दिया जा सकता। चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में पिछले वर्ष की तुलना में 14.5 प्रतिशत छात्रों की वृद्धि विश्वविद्यालयों में हुई थी। कोई भी देश इतनी वृद्धि सहन नहीं कर सकता परिणामस्वरूप बहुत से कदम उठाये गये हैं जिससे यह वृद्धि 1973-74 में घटकर 3 प्रतिशत रह गयी है।

इसके ग्रतिरिक्त पत्नाचार पाठ्यक्रमों ग्रौर स्नातक स्तर पर प्राईवेट छात्नों की संख्या 15 प्रतिशत बढ़ गयी है जिसका ग्रर्थ यह है कि नौकरी करने वाले व्यक्ति जो उच्च शिक्षा के लिए कालेजों ग्रादि का व्यय नहीं उठा सकते उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

यदि किसी कालेज में 400 से कम छात्र हों तो वह कालिज शैक्षिक तथा वित्तीय दृष्टि से सुचार ढंग से काम नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश इस प्रकार ग्रक्षम कालेज ग्रिधिकतर ग्रामीण क्षेतों में हैं। इन कालेजों में शिक्षा ग्रौर शिक्षकों का स्तर बहुत ही नीचा है। विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग ने इस स्थिति पर विचार किया है ग्रौर ग्रब उसने कालेजों में विकास के लिये एक सुविचारित नीति ग्रपनाना शुरू कर दिया है, जिससे कालेज ग्रनियंतित ढंग से न बढ़ते चले जायें तथा जहां कालेजों की संख्या बहुत ग्रधिक है वहां सहकारिता के ग्राधार पर शिक्षा दो जाए ताकि उपलब्ध संसाधनों का ग्रधिकतम उपयोग किया जा सके ग्रौर इसके साथ ही पाठ्यक्रमों का, विशेषकर गांवों में पुनर्निर्माण किया जायेगा।

कालिज स्तर पर विज्ञान के विकास पर ग्रायोग ने बड़ा जोर दिया है। यह कार्यक्रम चालू किया जा चुका है तथा इससे 111 कालेजों को लाभ हुग्रा है। इस कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों के सहयोग से वर्तमान ढांचे के ग्रन्तर्गत ही परिवर्तन कर पाठ्यक्रम का ग्राधुनिकोरकण किया गया है तथा उसका स्तर बढ़ाया गया है। यह ग्राशा की जाती है कि इससे राष्ट्रीय ग्रीर क्षेत्रीय ग्रावश्यकताग्री तथा छात्रों की ग्रावश्यकताग्री की बड़ी सामा तक पूर्ति होगी।

[प्रो॰ एस॰ नूरुल हसन]

परीक्षाम्रों में सुधार भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें म्रांतरिक निर्धारण, वर्गीकरण (ग्रेडिंग), उत्तीणं म्रोर म्रनुत्तीणं की परिपाटी को समाप्त करना तथा प्रश्न वैंक की पद्धित को लागू करना शामिल है। एक योजना स्वायत्तता प्राप्त कालेजों से भी सम्बन्धित है। कुछ कालेजों को नए प्रयोग करने की स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। वे स्थानीय म्रावश्यकताम्रों के म्रनुसार नए पाठ्यक्रमों पर प्रयोग कर सकेंगे म्रीर परीक्षा के स्तर में परिवर्तन भ्रौर सुधार कर सकेंगे।

मानव विज्ञान ग्रौर समाज शास्त्र के पाठ्यक्रम के विकास के लिए कई विशेषज्ञ सूचियां बनाई गईं तथा एक विज्ञान स्रनुसंधान परिषद् स्रौर वैज्ञानिक विषयों के सुपों पर विचार करने के लिए वैज्ञानिकों के दल स्थापित किये गये हैं। स्रायोग ने वैज्ञानिक स्रनुसंधान के लिये उपलब्ध संसाधनों के स्रन्तर्गत स्रन्-संधान सम्बन्धी समस्यास्रों पर बड़ा जोर दिया है। स्रायोग की सिकारिशों पर सरकार का सबसे महत्व-पूर्ण निर्णय विश्वविद्यालय ग्रौर कालेज के ग्रघ्यापकों के वेतनमान में सुधार करना है जिससे ग्रत्यधिक बौद्धिक उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति विश्वविद्यालयां में ग्रा सकें। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ग्रनुदान श्रायोग ने प्रारम्भिक भरती के लिए उच्च योग्यताएं निश्चित की हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्रांच्यापकों के अपनी अनुसंधान के लिये योग्यता बढ़ाने, अपनी जानकारी का स्तर बढ़ाने और सम्मेलनों, गोष्ठियों , ग्रीष्मकालीन स्कूलों ग्रादि में भाग लेने के ग्रवसर प्रदान करने के लिए ग्रनेकों प्रस्ताव रखे हैं। छात्रों को सुविधायें प्रदान करने के लिये ग्रत्यधिक प्राथमिकता देकर ग्रनेकों कार्यक्रम चालू किए गये हैं। इनमें सबसे पहला कार्यक्रम छात्रावासों को सुविधायें देना है। ग्रायोग छात्रावासों की निर्माण लागत को कम करने तथा छात्रावासों के निर्माण के लिये कालेजों स्रौर विश्वविद्यालयों को पर्याप्त सहायता देने के प्रस्तावों पर भी विचार कर रहा है । वस्तुतः गत कुछ वर्षों के दौरान लगभग 28000 छात्रों को छात्रा-वास सुविधायें प्रदान की गई हैं, जो कि सीमित साधनों को देखते हुए बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्रायोग ने पुस्तक बैंक स्थापित करने के प्रधान मंत्री के स्राह्मान को कार्यरूप देने के लिये स्रातेक कदम उठाए हैं। सहायता देने के लिए 2000 से ग्रधिक कालेजों की सूची बनाई जा चुकी है।

समाज के गरीज ग्रीर कमजोर वर्ग के युवकों की सुविधा के लिये ग्रघ्ययन केन्द्रों की स्थापना की गई है। ग्रनेक स्थानों पर गैर ग्रावासी छात्र केन्द्र खोले गये हैं। ग्रन्य कालेजों में भी छत्र सहायता निधियों की स्थापना की गई है, जिससे गरीब छात्रों को मदद दी जा सके। स्वास्थ्य केन्द्रों की ग्रोर भी ग्रायोग प्राथमिकता के ग्राधार पर घ्यान देगा।

ग्रन्य कदमां के साथ ग्रायोग ने ग्रंशकालिक व्यवसायिक पाठ्यक्रम का कार्यक्रम भी चालू किया है, ताकि छात्र एक ग्रच्छा व्यवसाय सोखने के लिये ग्रपने समय का सदुपयोग कर सकें।

मुझे ग्राणा है कि मानतीय सदस्य विश्वविद्यालयों के कार्यों में सुधार करने के लिये ग्रयने बहु-मूल्य सुझाव देंगे ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग के प्रतिवेदन पर चर्ची करते समय हमें देश में उच्च शिक्षा पर विचार विमर्श करने का ग्रवसर प्राप्त होता है । मैं माननीय मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1972-73 में सभा में प्रस्तुत किये गये इस प्रतिवेदन पर देश के प्रमुख समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया यही थी कि हमारी शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा, को एक गम्भीर संकट का सामना करना-पड़ रहा है ।

हमारी शिक्षा सम्बन्धी समस्याग्रों के बारे में जैसा कि माननीय मंत्री ने ग्रभी बताया है, देश में ऐसी शिक्षा प्रगाली लागू करके, जो नये वातावरण का निर्माण करे ग्रौर सामाजिक परिवर्तन लाने में प्रभावकारी सिद्ध हो, सीमित संसाधनों का ग्रधिकतम उपयोग किया जाना चाहिये। हम ग्रपनी शिक्षा प्रगाली पर द्रेश में ग्रन्य समस्याग्रों से ग्रलग हो कर विचार नहीं कर सकते, ग्रपितु हमें इस पर देश की वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों के संदर्भ में विचार करना होगा। मैं मंत्री महोदय के इस कथन से सहमत हूं कि प्रतिक्रियावादी शक्तियां ग्रपने राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये न केवल शैक्षिक संस्थाग्रों ग्रपितु छात्रों को भी ग्रपनी कठनुतली बनाये हुए थीं। हमें ग्रपनी शिक्षा प्रगाली पर न केवल देश की राजनीतिक परिस्थितियों ग्रपितु ग्राधिक परिस्थितियों के संदर्भ में विचार करना होगा, क्योंकि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धित युवा पीढ़ो की ग्राधिक समस्याग्रों को हल करने में विकल रही है ग्रौर इस से हमारे छात्रों में इस शिक्षा के विकद्ध विद्रोह की भावना भड़क उठी है। उन में ग्रनुशासनहीनता ग्रा गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा प्रसार की ऐसी योजना बनाने की अपनी जिम्मेदारी में असफल रहा है जो समाज के सभी वर्गों की इस प्रकार सहायता करे, जिस से सामाजिक उन्नित हो सके । देश भर में कालेजों में दाखिले का अनुपात 5.5 प्रति हजार है, जब कि दिल्ली में 13.6 प्रति हजार और उड़ीसा में 2.2 प्रति हजार है। इस से ज्ञात होता है कि शिक्षा मुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रामीण क्षेत्रों की अपेक्ष शहरी क्षेत्रों की और अधिक घ्यान दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करने में कमजोर वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ न्याय करना चाहिये।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि विषमता को दूर नहीं किया जा सकता है। यह एक गम्भीर ग्रसफतता है। हम हर ग्रवसर पर इस बात की दुहाई देते हैं कि ग्रसलो भारत ग्रामों में रहता है। परन्तु यह खेद की बात है कि हम ग्रामों में शिक्षा का प्रसार नहीं कर पाये हैं। उच्च शिक्षा पर विचार व्यक्त करते समय यह कहना ग्रसंगत नहीं होगा कि देश के ग्रायोजकों ने शिक्षा की ग्रत्यिक उपेक्षा की है। इस समय देश में ग्रशिक्षतों की भारी संख्या है। देश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रभी तक ग्रशिक्षत है। प्राथ- मिक शिक्षा के प्रति ग्रत्यिक उदासीनता बरती गई है।

हमारी शिक्षा तभी लाभदायक सिद्ध हो सकती है जब उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाये। इस समय स्थिति यह है कि हम डाक्टरों, इंजीनियरों और शिक्षकों को दूसरे देशों में भेज रहे हैं, मानो कि हम ने अपनी समस्यायें हल कर ली हों। यह हमारी आयोजना का दोष है। हम लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, परन्तु उन का सद्पयोग नहीं कर पाते। अतः हमारी पूरी योजना इस अकार बनाई जानी चाहिये कि शिक्षा संस्थाओं से निकलने वाले प्रत्येक छात्र का उपयोग किया जा सके। भूगर्म शास्त्रियों को प्रशिक्षण देने का क्या लाभ है यदि हम उन का उपयोग न कर सकें ? इसी प्रकार डाक्टरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें वेरोजगार रखने की कोई तक नहीं है।

हम ग्रापात की स्थिति से गुजर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में तेजी ग्रा रही है। ग्रतः परीक्षा सुवारों को भी तेजी से लागू किया जाना चाहिये ग्रीर परीक्षा सुधारों को इस ढंग से लागू किया जाना चाहिये कि शिक्षा संस्थाग्रों में छुरेबाजी तथा ऐसी ही ग्रन्य ग्रवांछतीय घटनायें न हों।

हमें खुशी है कि 20 सूत्री कार्यक्रम में छात्रों की समस्याग्रों पर उचित ध्यान दिया गया है। परन्तु यह कार्यक्रम कहां तक क्रियान्वित किया जायेगा ? क्या इस की क्रियान्विति में छात्रों के सहयोग

[स्रो सी० के० चन्द्रप्पन।

की श्रावश्यकता नहीं होगी ? श्रतः इस कार्यक्रम को लाग करने के लिए छात्रों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए ।

हमें सी॰ ग्राई॰ ए॰ की गतिविधियों से सतर्क रहना चाहिये। ग्रन्य देशों के समान ही भारत में भी साम्राज्यवादी ग्रमरीका की सी॰ ग्राई॰ ए॰ जैसी संस्थाये शिक्षा के क्षेत्र को ग्रपने कार्य के लिये ग्रिधक प्रभावकारी साधन मानती हैं। शिक्षा के क्षेत्र से उस के प्रभाव को समाप्त करने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, शिक्षा का उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना है। देश में शिक्षा का का उपयोग समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता श्रौर लोकतंत्र के संदेश को जनता में फैलाने के लिये किया जाना चाहिये।

साम्प्रदायिक तथा जातिवादी तत्वों का उन्मूलन किया जाना चाहिए । राष्ट्रोय स्वयं सेवक संघ, ग्रानन्दमार्ग तथा ऐसे ही ग्रन्य संगठनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, परन्तु हमारी शिक्षा संस्थाओं में उन की जड़ें ग्रभी भी जमी हुई हैं । उन के प्रभाव को शिक्षा क्षेत्र से हटाने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें ।

Shri Sudhakar Pandey (Chandauli): In the context of the present day situation in the country, the University Grants Commission's performance has been laudable and it deserves our congratulations.

The members of the University Grants Commission are great educationalists and they are doing appreciable work. But there is no full time Chairman of the Commission for the last many months. Shri Satish Chander is working as a temporary Chairman. He is doing good work. I want to know the time by which he will be made permanent Chairman and in case somebody else is to be appointed as permanent Chairman, the time by which he would be appointed. The appointment of the Chairman should be made early, because no organisation can function properly without its head.

The present situation is most favourable for the students who are serious about their studies. However, the anti-social elements are still active in the Universities. Such elements should be uprooted.

The Universities are functioning in their own way in the name of autonomy.

श्री एचः कें एल भगत पीठासीत हुए।

SHRI H. K. L. BHAGAT in the Chair.

The University Grants Commission should have control over the functioning of the Universities, but some elements which are active in the Universities, are polluting their atmosphere.

There are several Central Universities in the country. There should be proper co-ordination in the working of these universities. There should be a separate wing in the University Grant Commission for these universities.

We have not succeeded in introducing an educational system that may be in tune with the conditions obtaining in our country. There is all the greater need to set up more and more open universities in the country. We should also have workers' universities in the country. In big industrial concerns, a Mistry remains a Mistry all his life, though he may have more practical knowledge than an engineer. If that Mistry is provided with facilities to prosecute his studies after his duty hours, he can prove to be a very useful engineer for the country. His mental horizon can be widened and this way can get higher education.

Indian languages should be adopted as the media of instructions at the University level. These days, all the emphasis is being laid on English only. This should not be done. English should be treated like any other foreign language.

Higher education should be made the central subject. Then only we can bring about the needed improvement in our higher education.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): In our country, we have the same old educational system that had been introduced during British times. In the past, many educational commission had been appointed and they had made useful recommendations. What action has been taken to implement those recommendations? Although many attempts were made to bring about necessary changes in our educational system, yet, we have not been able to achieve our objective.

In some of our universities, there is gross mismanagement. It is said that there is great unrest in those universities, which get more funds from the University Grants Commission. For example, there is great unrest in Patna Univerthough it gets more funds whereas in Ranchi University, there is law and order in spite it is getting less funds.

Central Universities get lion's share from the funds of the University Grants Commission, whereas very limited funds have been made available to other Universities. The University Grants Commission should allocate funds to all the Universities on equal basis.

The teachers selected by the University Grants Commission should be imparted new training on the pattern of the training given to the I.A.S. and I.P.S. officers. Each University should be given grant in proportion to the number of students studying there and the population of the area served by it.

Universities should be reorganised on the basis of various subjects. For example, there should be separate universities for teaching agriculture, economics, arts, political science, medical science, etc.

Government should implement the recommendations made by the Central Education Advisory Board, which are very useful. Arrangements should be made in every college for teaching agriculture, commerce and character-building.

Education should be made the central subject. The number of Central Universities should be increased so that there may be at least one Central University in each State.

[Shri Shankar Dayal Singh]

There should be uniform syllabuses. Text-books should be made available to the students at cheap rates, as per the announcement made by the Prime Minister.

The services of the University teachers should be transferable from one University to the other. An Expert Committee should be set up to make education more practical.

There is no female member in the University Grants Commission. The one-third of the members of the Commission should be ladies.

At present, we need not only technical education but practical education as well. The students should be imparted such an education as may prove useful to them in their later life.

प्रो० नारायण चन्द पराज्ञार (हमीरपुर): विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग ने ग्रपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया है कि ग्रायोग के पास निधियों की कमी के कारण प्रतिभावान व्यक्तियों की प्रतिभा के ग्रनुकूल उच्च शिक्षा प्रणाली के विकास तथा देश के विकास में प्रमुख भूमिका निभाने की संभावनाग्रों में बाधा पड़ी है। सरकार को ग्रवश्य विचार करना चाहिए कि योजना ग्रीर गैर-योजना के लिए विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग को दिए गए धन में कैसे पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है ताकि इससे सुपरिणाम निकल सकें।

पी० एच० डी० करने के लिए लोग ग्रत्यधिक लालाधित हो रहे हैं। पी० एच० डी० ग्रौर विशेष योग्यताग्रों के नाम में कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रनेक ग्रयोग्य व्यक्तियों की भीड़भाड़ हो गई है लेकिन वहां क्षेत्रीय लोगों को स्थान नहीं मिलता है। इससे वहां के स्थानीय लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ ग्रन्याय हो रहा है। विशिष्ट क्षेत्र के संस्कृति ग्रधान लोगों की ग्रोर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्रापात स्थिति की उद्घोषणा तथा 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के बाद समुचे देश के विश्वविद्यालय परिसरों में शान्ति का वातावरण पैदा हो गया है। लेकिन शिक्षकों या छात्रों को शरारत करने के लिए भड़काने वाले कुछ लोग कहीं पर छुप गये हैं। जब तक सरकार उन सभी तत्वों को जिन्होंने इस सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को ठप्प करने हेतु जय प्रकाश नारायण को ग्रामंत्रित किया, जेल में नहीं डालेगी तक तब देश मुरक्षित नहीं है। मंत्री महोदय को इस मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। उन्हें विशेषतया यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संदिग्ध गति-विधियों वाले व्यक्तियों को उनके वर्तमान पदों पर नहीं रखा जायेगा।

शिक्षकों तथा कुलपितयों की नियुक्ति, पदोंन्नित तथा सेवा निवृति के मामले में समानता होनी चाहिए। 70 वर्ष की ग्रायु से ऊर वाले व्यक्तियों को कुलपित के पदों पर बनाये रखने का कोई ग्रीचित्य नहीं है जबकि ग्रधिकांश राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय सरकार ने कुलपितयों को 65 वर्ष की ग्रायु में सेवानिवृत करने का निर्णय किया है।

प्रधान मंत्री ने पुस्तक-कोषं का उल्लेख किया है। लेकिन ये पुस्तक-कोष तभी सहायक सिद्ध हो सकते हैं यदि क्षेत्रीय भाषात्रां में अच्छी पाठ्य पुस्तकों लिखी जाये। विश्वविद्यालय श्रनुदान ग्रायोग या मंत्रालय में एक ग्रलग विभाग बनाया जाना चाहिये जो यह सुनिश्चित करे कि विभिन्न क्षेत्रिय भाषाग्रो में श्रच्छी पाठ्य पुस्तके लिखी जायें।

श्री जी० विश्वनाथन् (वान्डीवाश) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि अकादमीय एंव व्यावसाय पाठ्यक्रमों में अधिक शतः उच्च शिक्षा विशेषकर पूर्वस्नातक स्तर पर, छात्रों की आवश्यकताओं उनकी योग्यताओं एवं अभिरूचियां तथा देश की विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यवताओं के अनुरूप नहीं है। यह तो हमारे देश में शिक्षा संस्थाओं, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के कार्यकरण का सारांश प्रतिपादित करती है। हम गत चार वर्ष से अपने वर्तमान शिक्षा मंत्री से बड़ी आशाएं एंव शीघ्र पारिणामों की अपेक्षा कर रहे हैं।

सरकार ने पांडिचेरी में एक विश्वविद्यालय खोलने का वचन दिया है, जो स्रभी तक पूरा नहीं हुस्रा है। स्राशा है यह विश्वविद्यालय शीघ्र ही कार्य स्रारंभ कर देगा।

हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न प्रकार का है। विभिन्न शिक्षा आयोगों ने बताया है कि विश्वविद्यालयों से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर स्नातक योग्य नहीं पाये गये है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस मामलें पर सभी विश्वविद्यालयों से विचार विमर्श करना चाहिए यद्यपि ये विश्वविद्यालय राज्य सरकारों या अन्य प्राधिकरण द्वारा नियंतित है। मेरे विचार से मंत्री महोदय को इस विश्य पर गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिये।

शिक्षा की गुणक्ता पर विचार करने समय हमें छात्रों को ही ध्यान में रखना होगा। छात्र अध्यापक सम्बन्ध शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन इस प्रतिवेदन से पता चलता है कि छात्र के विषय में अध्यापक को कुछ मालूम नहीं होता उनमें आपसी निकटता का अभाव रहता है। इन सम्बन्धों को सुदृढ़ करके हम शिक्षा के स्तर में सुधार कर सकते है। साथ ही साथ छात्रों में अनुशासन की भावना भी पैदा की जा सकती है।

प्रध्यापक को यदि छात्र की पृष्टभूमि का पता हो तो छात्र की गलतियों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। उसकी समस्याग्रों का ग्रन्दाजा लग सकता है। विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में छात्रों को भागीदार बनाने के विषय में भी कहा गया है। मुझे प्रसन्नता है कि केरल में ऐसा किया जा रहा है। एक ग्रन्य प्रश्न यह उठाया गया है कि छात्र ग्रध्यापकों का मूल्यां-कंन करें। पहले ही छात्र राजनीति में बहुत घुसते जा रहे है। ग्राज इस स्थिति के लिये हम सभी दोषी हैं। सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि छात्र हमारे साथ जायें। ग्रब समय ग्रा गया है कि हम विश्वविद्यालयों ग्रीर कालेजां को राजनीतिक ग्रखाड़े न बनायें।

शिक्षा के स्तर को बनाने ग्रौर बिगाड़ने में शिक्षक का ग्रिधिक हाथ होता है। सारे देश का भविष्य उसके हाथ में है। शिक्षक ही छात्रों में ग्रनुशासन की भावना भर सकता है, उनका चरित्र निर्माण कर सकता है। लेकिन उपदेश मात्र से कुछ नहीं होता। शिक्षक को स्वयं इन गुणों को धारण करना चाहिये।

[श्री जी० विश्वन थन]

शिक्षका की कुछ भ्रपनी मांगे हैं। इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि शिक्षक का वेतन श्रच्छा हो श्रौर उसे श्रन्य श्रावश्यक सुविधाएं प्रदान की जायें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होस्टलों तथा ग्रंथालयों पर ध्यान अवश्य दे रहा लेकिन कालेज की ग्रंथालय या होस्टल के लिये केवल 50,000 रूपये दिये जाते हैं। यह राशि नितान्त अपर्याप्त है। विश्वविद्यालय अनुदान को पर्याप्त धन दिया जाना चाहिये।

मंत्री महोदय काफ़ी समय से शिक्षा में सुधार की बातें करते ग्रा रहे हैं लेकिन इन्हें किया कब जायेगा। ग्राप कहते है कि वर्तमान शिक्षा पद्यति पुरानी पड़ गई है लेकिन उसका विकल्प क्या सोचा है। क्या हम ग्रुप्रेजों की चलाई हुई प्रणाली ही जारी रखेंगे। ग्रब देश की ग्रावश्यकतानुसार शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिये।

Shri Rudra Pratap Singh (Barabanki): I fully support this Bill. Prof. Nurul Hasan is an efficient Minister and takes much interest in the educational affairs. I want to draw the attention of this august House towards the sense of discipline. It is the discipline which moulds the character of the student and the student of today is the nation-builder of tomorrow.

First of all we have to take into account the causes of indiscipline. Schools, Colleges and Universities are a part of the society so the matter relating to discipline cannot entirely be left to the Education Ministry. There are certain vested interests which utilise students for their own selfish end directly or indirectly. I can cite the example of J. P. who misguided the students. The people of India will not excuse J. P. for the havoe, he has played with the society.

I am fully convinced that the Prime Minister's own conduct will act as a lighthouse for the ship of the nation. It will continue to inspire the general masses. No doubt we want to provide equal rights to women in this International Women Year, but this does not mean that our youngmen should keep long hair and wear dresses like girls. This will not in any way help us in building the nation.

Even to-day untouchability is being practised in our educational institutions in some form or the other. Although steps are being taken by Government yet much remains to be done.

There should be students participation in the management of the Colleges. They should also be entrusted with some responsibility and they will feel that they have a hand in the working of their institution. The Prime Minister has said in her 20-point programme that students will get books on fair price and hostelers will get essential commodities on fair prices. It is very good.

Unemployment is one of the most acute problems facing the country. The students feel that there is no future after completing the education. I am happy that the Prime Minister has promised to wipe out unemployment in her 20-point programme.

I am hopeful of a bright future under the able leadership of Mrs. Gandhi and a new India will emerge.

श्री ध.मनकर (भितंडी): सभापति महोदय सैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1972-73 के दौरान किये गये कार्य की सराहना करता हूं । इस बार का प्रतिवेदन एक अलग किस्म का है, परम्पर से हट कर है। इस बार प्रतिवेदन में कई महत्वपूर्ण बातें जोडी गई हैं जैसे विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में कितना-कितना अनुदान दिया गया आदि।

विज्ञान पर बढ़ाया गया व्यय तो समझ में स्राता है लेकिन इसका यह स्रर्थ नहीं कि मानविकी पर किये जाने वाले व्यय को कम किया जाये।

छ त्रं के ऐसी शिक्षा दी जाते जिसमें वे ग्रागे चल कर कोई व्यवसाय श्रपना सके। रोजगारी न्मुख शिक्षा ही बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा दिला सकती है। विश्व-विद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मशालाग्रों, मुर्गीपालन के फ़ार्म ग्रादि खोले जाने चाहिये।

श्रनुसूचित जातियों, श्रनुसूचित जनजातियों तथा श्रादिवासियों द्वारा चलाये जा रहे कालेजों का स्रिधक सहायता दी जाये। रोजगार की नई योजना श्रोर की श्रोर भी विश्वविद्यालय श्रनुदान श्रायोग द्वारा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। ऐसी एक योजना हमारा कालेज भी भेज रहा है। विश्वविद्यालय श्रनुदान श्रायोग ने काफ़ी समय पहले उन कालेजों को वित्तीय सहायता देने की बात मान ली थी जो श्रनुसूचित जातियों तथा श्रनुसूचित जनजातियों के छातों के लिये विशेष रूप से शिक्षा का प्रबन्ध कर रहे हों। हम पिछले सात वर्ष से श्रनुसूचित जातियों तथा श्रनुसूचित जनजातियों के कमजोर छात्रों को पढ़ा रहे है ताकि वे कक्षा के श्रन्य विद्यायियों के साथ चल सकें।

विश्वविद्यालय श्रनुदान श्रायोग द्वारा वालेजो को दी जाने वाली राशि बहुत कम है। इसे बढ़ाया जाये।

श्रव मैं भिवंडी कालेज के बारे में कुछ कहना चहता हूं। मंत्री महोदय जो महान शिक्षाविद् है, वे वहां श्राये श्रीर देखें कि हमारें कालेज में कैसी हिन्दू-मृस्लिम एकता है। यह एक माडल स्कूल है। भिवंडी में इतने दंगे हुए लेकिन छात्र चाहे हिन्दू हां या मुसलमान श्रापस में मिल कर रहे। कालेज राष्ट्रीय एकता का नमूना है। सरकार को ऐसे कालेजों की श्रीधक सहायता देनी चाहिये। नये श्राधिक कार्यक्रम को लागू करने के लिये ऐसा श्रवश्य उपाय किया जाना चाहिये।

एक अन्य बात यह है कि छात्रों के लिये सस्ते होस्टल खोले जाये। बड़े कमरे हो जिनमें 6 तक छात्र एक साथ रह सकें।

इन शब्दों के साथ में प्रतिवेदन की सराहना करता हूं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Some Members have rightly pointed out that there is a need for radical changes in the education system. We have been say-

[Shri Ramavatar Shastri]

ing all this for the last so many years but our achievements are far from satisfactory. Programmes should be implemented effectively.

Secondly reactionary elements are infilterating the educational institutions. These elements are available both in the teacher as well as the student community. They should be weeded out speedily.

It is true that certain arrests have been made but a large number of miscreants are still at large. I am unable to understand why the Vidyarthi Parishad has not been declared an illegal body.

The University Grants Commission had visited Patna in March or April A delegation on behalf of the students and teachers apprised the Commission of their basic problems. Now the Government have come forward with a programme to provide books and food at cheap rates. This is indeed a welcome step. But there is need to pay attention towards improving the conditions prevailing in the hostels. Inspite of the fact that the University Grants Commission has given rupees 19 lakhs to the Patna University, the hostel accommodation there is not enough. Not only that the science students in the university do not have proper equipment for experiments. This is because of poor financial position of the University. I have been advocating for establishment of Central University in each state. If Patna University is made a Central University, the situation may improve,

It is a matter of regret that the University Grants Commission does not pay proper attention towards Colleges located in rural areas. In many educational institutions the salaries of teachers are paid, are very late. Government should ensure that the payment of salary is made at proper time.

The condition of non-teaching staff of the Universities is very miserable. They have some genuine grievances. It is high time those grievances are redressed. If our Government discharge its obligations towards educational institutions sincerely, they will get cooperation from all sides.

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj): The Report of University Grants Commission for the year 1972-73 was presented in the House in 1974 and now in 1975 it is under discussion. Since then great changes have taken place in the country and many of the things contained in the report have become out of date.

There is urgent need for complete overhaul of the present system of education. Unfortunately the University Grants Commission has failed in this regard. Our education is not job-oriented. Number of unemployed youth is atincrease. Moreover, political parties are exploiting them for political motives.

In our country 85 to 90 per cent people live in villages. Therefore, there is great need for providing educational facilities in rural areas.

It is a matter of gratification that scholarships and books will be provided to poor students.

Although our party and leader say much about giving encouagement to Urdu language, our Government have not yet been able to make Jamia Milia an Urdu University. May I know what are the reasons therefor?

The conditions in Mithila University are very unsatisfactory. Immediate attention should be paid to bring about improvement there.

There are about 16 regional engineering colleges in the country. They should be run on the line of Indian Institutes of Technology, so that they can prove more useful for the country.

श्री लिज़्लाधर कटकी (नवगांव): विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन पर ऐसे समय में चर्चा की जा रहीं है जब कि देश में ग्रापातकालीन स्थिति है। छात्रों की ग्रपनी कुछ शिकायतें हैं ग्रीर उन्हें दूर करने के लिए यह उचित समय है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को न केवल विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की शिक्षा को बिल्क सारे देश की शिक्षा को दिशा प्रदान करनी है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कियान्वित करना आवश्यक है।

20 सूत्री कार्यक्रम में 3 सूत्र छात्रों से सम्बन्धित हैं। इनमें से एक सूत्र विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु प्रशिक्षता योजना शुरु करने के बारे में है। इस दिशा में कार्य शुरु हो गया है। इस प्रतिवेदन से पता चलता है कि यह योजना 45 विश्वविद्यालयों एवं 18 महाविद्यालयों में लागू है। लेकिन इस कार्य के लिए आवटित राशि पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह सुविधा प्रत्येक छात्र को दी जाए और इसके लिए हमें अधिक ससाधन जुटाने होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष सबसे बड़ी रुकावट धनाभाव है।

छात्रों में अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, उदाहरणार्थ राष्ट्रीय अनुशासन योजना—राष्ट्रीय केडट कोर तथा भारत स्काउट्स तथा गाइड्स । छात्र-छात्राओं के लिए इनमें से एक योजना चुनना अनिवार्य होना चाहिए ।

शिक्षा को रोजगार प्रधान बनाया जाना चाहिए। शिक्षा ग्रायोग का कहना है कि यदि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा दी जाए तो विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन इसका कहना है कि शिक्षा का विषय राज्य सूची में ग्राता है, इसलिए ग्रायोग इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरा सुझाव है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया जाए ताकि संसद इसके बारे में कानून बना सके। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

यन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। यदि हम स्त्रियों को शिक्षितः नहीं करो तो हम भविष्य में अच्छे नागरिकों की आशा किस प्रकार कर सकते हैं? जहां तक छाताओं के लिए छात्रावास सुविधाओं का प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुल लागत का 75 प्रतिशत देता है और शेष 25 प्रतिशत राज्य को जुटाना पड़ता है। हम ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धन छाताओं के लिए सस्ते छात्रावास बनाने चाहिए और उन्हें वहां खाना पकाने की सुविधा देनी चाहिए।

[श्रीं ली.लाधर कटकी]

हुमें बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 18 के ग्रंतर्गत ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि गरीब लड़िकयों को ग्रंपना खाना बनाने की सुविधाए भी दी जायें।

श्री ग्ररिवन्द वाल पजनोर (पांडिचेरी): ग्राज की स्थिति में हम ग्रनुदान विश्वविद्यालय ग्रायोग के प्रतिवेदन पर ग्रब भली प्रकार विचार कर सकते हैं। ग्रब शिक्षा के क्षेत्र में ग्रच्छे वातावरण का ग्रारंभ हो गया है। स्वतत्रता के 27 वर्ष पश्चात् की स्थिति का ग्रध्ययन करने से हम ग्रनुभव करते हैं कि उच्च शिक्षा के बारे में ग्रभी भी ग्रनिश्चितता बनी हुई है। उच्च शिक्षा की कठिनाइयों तथा बुराइयों को तो हम जानते हैं लेकिन हम उसका समाधान नहीं कर पाते।

1958-59 में जब मैं विधिविद्यालय में पढ़ता था तब एक सेक्शन में 715 छात्र थे। परन्तु ग्राज भी ग्रान्ध्र प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में प्रात:कालीन कक्षाग्रों में 1,600, दिन की कक्षाग्रों में 1,200 तथा सायकालीन कक्षाग्रों में 1,600 छात्र हैं जबिक वहां केवल 10 प्रतिशत छात्रों के लिये ही पर्याप्त स्थान है ।

यदि हम विद्यार्थियों को कालेजों में उचित पाठ्यक्रमों द्वारा पढ़ाई में व्यस्त रख सकें तो उनका ध्यान राजनीति ग्रादि की ग्रोर नहीं जायेगा। खेलकूद को उचित महत्त्व दिया जाना चाहिए। हर संस्था में खेलकूद प्रशिक्षण हेतु सुविधाए होनी चाहिए।

परीक्षा प्रणाली में भी कुछ खराबी है। ग्रयोग्य लोग एम०ए० तथा डांक्टोरेट में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाते हैं। मूल्यांकन की वर्तमान प्रणाली में सुधारों की ग्रावश्यकता है।

हमें ग्राम्य क्षेत्र की शिक्षा समस्याग्रों पर भी विचार करना चाहिए। वे भारतीय प्रशासिन के सेवा की परीक्षा में शहरी लड़कों की तुलना में ग्रच्छे ग्रंक नहीं प्राप्त कर पाते। उन लोगों को ग्रिखल भारतेय स्तर पर ग्राने के ग्रवसर दिये जाने चाहिए। ग्रध्यापन कार्य में सुधार करने के उद्दश्य से ग्रिखल भारतीय कार्यक्रम शुरु किये जाने चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटेन, ग्रमरीका, रूस जापान ग्राद्धि देशों से हमारा सहयोग है। लेकिन फ़ांस से प्राशिक्षण ग्रौर प्रद्यौगिकी के बारे में हमारा कोई भी सहयोग नहीं है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि देश के एक कोने का विद्यार्थी दूसरे कोने के विद्यार्थी से बातचीत कर सके । यह अत्यन्त आवश्यक है । हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्त्व देना चाहिए लेकिन तकनीकी ज्ञान के लिये एक अंतराष्ट्रीय भाषा की भी आवश्यकता है ।

श्री पी॰ एंथनी रेड्डी (ग्रनन्तपुर) : विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन के ग्रवलोकन से पता चलता है कि शिक्षा प्रसार के क्षत में ग्रपार प्रगति हुई है।

शिक्षा मंत्री तथा विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग को शिक्षा का स्तर उठाने तथा कालेजों ग्रौर विश्वविद्यालयों में ग्रन्छे वैज्ञानिक उपकरण प्रदान करने के लिये नये कालिज ग्रौर विश्वविद्यालय खोलने का कार्यक्रम कुछ समय के लिये स्थगित कर देना चाहिए। कालिजों तथा छातावासों मे ग्रन्थालय, ग्रावास ग्राह्म की ग्रधिक सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए।

हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली बहुत पुरानी है, ग्रौर अग्रेजों के समय से चली ग्रा रही है। इससे युवकों को केवल वर्लक बनाने की प्रेरणा मिलती है। हमारे नागरिक ग्रात्मनिर्भर बने इसके लिए हमें ग्रपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना पड़ेगा। हर कालिज में विद्यार्थियों की रुचियों तथा गुणों का ग्रध्ययन करने के लिये एक मनोवैज्ञानिक होना चाहिए जो उनका मार्गदर्शन कर सके ग्रौर ग्रपनी रुचि तथा गुण के ग्रनुसार ग्रध्ययन करने के बाद वे ग्रपने पैरों पर खड़े होकर ग्रात्मनिर्भर बन सकें।

मैं स्वायत्तशासी कालिज के विचार का समर्थन करता हूं। अब तक हम विद्यार्थियों को किसी परीक्षा के लिये पढ़ाने की ओर ध्यान देते रहें हैं। हमने उन्हें सर्वागीन शिक्षा प्रदान नहीं की है। यदि कालिज स्वायत्तशासी हों तो हम विद्यार्थियों को सर्वागीन शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य में एक स्वायत्तशासी कालिज सरकार तथा एक प्रख्यात शिक्षा केन्द्र के नियंत्रण में खोलकर इस दिशा में एक प्रयोग किया जा सकता है। हम कुछ वर्षों तक इन कालिजों के कार्यकरण का अध्ययन कर सकते हैं और यदि यह प्रयोग सफल हो तो हम देश में बड़े पैमाने पर लागू कर सकते हैं।

Shri P. Ganga Reddy (Adilabad): We should have a national policy for education. Taking all these things into consideration education should be made a central subject or at least brought under concurrent list.

There is restlessness, dissatisfaction and extreme indiscipline among the students. They do not give any importance to studies. It has become difficult to distinguish between man and woman as far as their dressing habits, etc, are concerned. Immediate action should be taken to have regulations regarding hair cutting, dress, etc., and discipline should be enforced.

Some of my friends have stated that Public Schools are luxurious and we should do away with them. But my submission is that we should make an attempt to raise the standard of other schools rather than to do away with the institutions which are functioning quite satisfactorily. At the same time, my submission is that we should pay more attention to vocational and technical education so that our young men could be able to earn their livelihood after completion of their education.

More attention should be given to the sports in colleges. It is a matter of grave concern that our country failed to snatch even a single Gold Medal in Olympic games. Necessary facilities for the games and sports should be provided so that our students may not be able to spare time for participation in political or politically, motivated agitations. Military training should be made compulsory for the students. It will only help in enforcement of discipline among the students but will also infuse in them the sense of patriotism.

Regarding the recruitment of teachers, it is submitted that only intelligent and talented people should be recruited in this profession because as a matter of fact, the teachers are the real builders of the nation and utmost care should be taken in their recruitment. I welcome the government decision for giving aid to the scientific research scholars for writing books. The facilities of a steno or an

[Shri P. Ganga Reddy]

assistant should also be provided to doctors and engineers. More funds should be made available for rural colleges. Urdu is the language of our country and more attention should be paid for its propagation and expansion in the country.

श्रीमती रोजा देशपाँडे (बम्बई मध्य): मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि शिक्षा पद्धित में ग्रामूल परिवर्तन की ग्रावश्यकता है। हमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में सुधार करना होगा। यह सच है कि हमारी शिक्षा रोजगार-प्रधान होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को केवल स्नातक ही नहीं तैयार करने चाहिए। उन्हें शिक्षा इस ढग से मिलनी चाहिए जिससे वे ग्रनुभव करें कि देश के प्रति इनका भी कोई कर्तव्य है।

यह वर्ष ग्रंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है ग्रौर मैं जानना चाहती हूं कि ग्राप इस वर्ष महिलाग्रों के लिए क्या करने जा रहे हैं। गांवों में लड़िकयों को पढ़ाया नहीं जाता। गांव के लोग ग्रपनी लड़िकयों को स्कूलों में भजने के प्रति उदासीन हैं। हमें देश के बड़े बड़े जिलों में कुछ महिला कालेज, स्कूल तथा छात्रावास बनाने चाहिए।

हमारे देश में ग्रनेक विद्यापीठ, कालेज ग्रौर विश्वविद्यालय हैं। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन संस्थाओं का प्रजातंत्रीयकरण हो और उन्हें चलाने में ऋध्यापकों, प्रोफेसरों तथा विद्यार्थियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए । मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहती हू । कोल्हापुर में एक मौनी विद्यापीठ है ग्रौर यह काफी बड़ा विद्यापीठ है। केन्द्र सरकार भी इसे 2 लाख रुपये का अनुदान दे रही है। महाराष्ट्र सरकार भी इसे अनुदान देती है लेकिन यह श्री दी० पी० पाटिल और श्री मुलगांवकर की निजी सम्पत्ति बन गया है। इस कालेज में एक विद्यार्थी की हत्या कर दी गई है श्रीर इस वारे में मैंने शिक्षा मंत्री जी को तार दिया था कि वह इसकी जांच कराए। इस विद्यार्थी की हत्या श्री मुलगांवकर के ग्रांगरक्षक द्वारा की गई है। प्रत्येक दल इस हत्या के बारे में गंभीर है। ऐसे विद्यापीठ को चलाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है ? इस विद्यापीठ में कई बहुत अच्छे शिक्षाविद थे लेकिन उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया । विद्यापीठ के प्रोफेसरों को वेतन नहीं दिया जा रहा । इस विद्यापीठ के जो मालिक बने बैठे हैं वह वेतन देना ही नहीं चाहते। इसीलिए मैं बार बार इस बात पर बल दे रही हं कि इस संबंध में जांच कराइ जाए । सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ही विधान होना चाहिए ताकि .. स्रध्यापक, प्रोफेसर तथा विद्यार्थी भी विभिन्न संस्थास्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सके स्रौर विद्यार्थी स्रपनी शिक्षा संबंधी फठिनाइयों को अध्यापकों के समक्ष रख ाकें। स्कूलों और कालेजों में समान पुस्तकें नहीं लगाई जाती। किसी कालेज में कोइ एक किताब लगती है तो दूसरे कालेज में दूसरी लगती है। स्कूलों ग्रौर कालेजों के लिए समान पुस्तकें निर्धारित की जानी चाहिए। इतिहास ग्रौर राजनीति पढ़ाने के लिए देश भर में एक ही प्रकार की प्रणाली होनी चाहिए।

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर): यह सर्वविदित है कि शिक्षा राज्य का विषय है लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिक्षा के स्तर में विशेषकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार करना होता है और जब तक इसके कार्य के लिए समुचित नियंतण और शक्ति आयोग को नहीं दी जाती वह अपने कार्य में सकल कैंसे हो सकता है अतः शिक्षा मंत्री को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिक शक्ति और समन्तयन कार्य देने पर विचार करना चाहिए तािक वह अपना काम ठीक तरह से कर सके। शिक्षा मंत्री यह कार्य दो प्रकार से कर सकते हैं एक तो शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को अनुरोध

करके ग्रौर दूसरा विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग को दी जाने वाली राशि में कमी करके—कुछ मामलों में विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग ग्रनुदान न दे ग्रौर इस प्रकार वह नियंत्रण रख सकता है। लेकिन यह उचित तरीका नहीं है। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार के लिए विस्तृत उपाय किए जाए।

प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा को एक समेकित प्रक्रिया के रूप में देखा जाए। यह भी कहा गया है कि कालेजों का विकास ग्रनियमित है लेकिन यह विषय राज्य सरकार का है ग्रीर इस पर न तो केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का ग्रीर न ही विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग का कोई नियंत्रण है। विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग तो केवल ग्रनुदान देता है ग्रीर ग्रपने सीमित संसाधनों के साथ वह शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं कर सकता ग्रतः इस सम्बन्ध में उचित योजना की ग्रावश्यकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है अनुसंधान और प्रकाशन कार्यों पर अधिक बल देने के कारण शिक्षा के उचित विकास और सुधार में रुकावट आई है और अनुसंधान भी एक सीमा तक घिसा पिटा सा लगने लगता है। विद्यार्थियों को अनुसंधान कार्य के समाप्त कर लेने के बाद भी सहायक विषयों का ज्ञान नहीं होता। विदेशों में कुछ विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य करने वाले विद्यार्थियों को सहायक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कक्षाओं में जाना पड़ता है। हमारे यहां भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

विभिन्न विखिविद्यालयों के विद्वानों द्वारा जो अनुसंधान कार्य किया गया है इस बारे में न तो शिक्षा मत्रालय ने और न ही विखिविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ प्रकाशित किया है। अब यह कार्य होल ही में बड़ौदा विश्वविद्यालय को सौंया गया है और इसके लिए 10,000 रुपये का अनुदान दिया गया है। यह राशि पर्याप्त नहीं है। मैं यह सुझाब देना चाहता हूं कि विख्वविद्यालय अनुदान आयोग इस कार्य को अपने हाथ में ले ले क्योंकि इससे अनुसंधान करने वाले विद्वानों का ज्ञानवर्धन होगा।

विभिन्न विश्वविद्यालयों को पुस्तकालयों के लिए अनुदान दिया गया है लेकिन ऐसा कोई भी विशेष पुस्तकालय नहीं है जहां कि विश्व विख्यात भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध हों कुछ विश्वविद्यालयों में ऐसे पुस्तकालय भी होने चाहिएं जहां विश्व भर के साहित्यिक प्रकाशन उपलब्ध हों।

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur): The U.G.C. report for 1972-73 is before us. It is correct that there has been vast expansion of education in the country during these years. But it is a sad development that politics and indiscipline has marred our educational system. I think its remedy is that there should be selective admission in the universities. I also think that a ban should be imposed at least for the next 15 years on the formation of students unions.

Although education is a nation-building item, but still it has harmed the nation more than building it. If U.G.C. has not got adequate powers under the Constitution, they should be saddled with more powers so that they can direct the State Governments to stream line their education system. I further feel that education should be made a concurrent subject if the State Government's are not prepared to hand it over to the Centre. U.G.C. disburses crores of rupees to the Degree Colleges for hostels, libraries, buildings, etc., but it does not have any cell or squad to see that the funds disbursed by them to the Degree Colleges

[Shri Rajdeo Singh]

are utilised properly. Therefore a cell or squad should be set up for this purpose.

There are twelve members in U.G.C. and if each member is allocated a different subject to deal with, its functioning will become more efficient.

There are several rural degree colleges in our country but the standard of education there is inferior. Competent professors hesitate to go to rural areas because they don't get the same facilities which they get in urban areas. They have to face the problem of accommodation also. In order to improve their standard the U.G.C. should give liberal help to rural degree colleges on a priority basis for building staff quarters and hostels.

With these words I support this report.

Shri B. R. Shukla (Bahraich): The present emergency in the country has provided a good opportunity to the Ministry of Education to introduce reforms in the system of Education prevalent in this country. There is no disturbance in the university campus these days. Sense of discipline has grown in the minds of students,. Teachers and students have realised that hooliganism will not be tolerated. Some professors have been arrested for their association with R.S.S. or with anti-social elements. The Minister of Education should make amendments in the Education Code so as to provide for the termination of services of such professors.

It is being emphasised these days that practical tests should be held as internal tests in universities. I do not support it. In fact tutorial and internal examinations held in colleges and universities do not help much the meritorious students. The vested interests have flourished so much in universities these days that they manage to get things done as they like.

There are certain colleges affiliated to B.H.U. which are functioning in the city outside the university campus and the teaching staff working in these colleges do not get the central pay scales. They are getting the U.P. Government pay scales. They are not getting even the new pay scales as recommended by the U.G.C. This has created great anomaly and it should be removed.

The Banaras Hindu University has been a stronghold of R.S.S. and litigation have been going on in regard to certain matters there. This emergency should be utilised to abolish these elements from the university for all time to come.

In the last I would like to submit that the Ministry of Education as well as U.G.C has done a lot to streemline the educational structure.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) The University Grants Commission should be made the highest institution in the field of education. The U.G.C. has been a failure due to certain legal lacunas as well as inadequate exercise of the powers given to it. I submit that the U.G.C. should not only undertake the job of disbursing grants to educational institutions but also devote more attention to the development of educational facilities in the rural areas. Otherwise the village students who cannot come to urban areas for higher studies will be deprived of

higher education. Our backward areas will remain backward. I want to know how many colleges and universities have been opened in rural areas. If any college has been set up it doesn't have the hostel facility Therefore I request that U.G.C. should pay more attention to the development of educational facilities in rural areas. The Education Minister had given an assurance two years back that a probe would be made into the working of deemed universities but nothing has been done so far.

The Birla Institute of Technology and Science has become an institution of minting money and evading taxes. The plight of teachers there is pitiable. Out of 198 Faculty members 94 are temporary. For the last ten years they are on temporary posts. It is completely a mismanaged institution. Neither the Ministry of Education nor the U.G.C. have taken any measures to set things right there. The U.G.C. has rather continued to disburse grants to them. Moreover huge donations are being made to the Birla institutes. All these donations are tax free. The hon. Minister has said that—

"Each of the following amounts has been or will be allowed as deduction in computing the income of the payer and therefore will be completely exempted from tax."

These people evade tax in this form and spend less. In 1970-71 their estimated budget was 81 lakh and 28 thousand but they spent only 64.82 lakh. Likewise in 1972-73 their estimated budget was of 83.11 lakh rupees but only 66.27 lakh rupees were spent out of it. No institution of any deemed university has received so much amount of money.

The funds disbursed by U.G.C. to various institutions are not being properly utilised. There should be more effective control on it. The Ministry of Education should make an enquiry as to how these funds are being utilised.

प्रो० एस० नुरूल हसन: मैं माननीय सदस्यों का ग्रह न्त ग्राभारी हूं कि उन्होंने उच्च शिक्षा के मामले में तथा विश्वविद्यालय ग्रनुपान ग्रायोग के कार्यों में इतनी रुचि दिखाई है ग्रौर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं यद्यपि समय की कमी के कारण मेरे लिए इन सभी सुझाग्रों के बारे में उत्तर देना सम्भव नहीं है परन्तु इसका यह ग्रर्थ नहीं लगाना चाहिए कि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं उन सभी सुझावों पर विचार करूंगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने सीमित ससाधनों के साथ अर्थात् जो कुछ उसे यह सदन देने में समर्थ हुआ है बहुत अच्छा काम कर दिखाया है वित्तीय कठिनाइयों के कारण शिक्षा मंत्रालय को दिए जाने वाले अनुदानों में भारी कटौती करनी पड़ी। जहां तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी गई राशि का सम्बन्ध हैं उसमें सबसे अधिक कटौती की गई है अतः आयोग को कई ऐसे कार्यक्रमों को जिन पर कि कार्य किया जाना चाहिए था और जिन्हें आयोग हाथ में लेना चाहता था, स्थिगित करना पड़ा। पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 210 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। मेरे विचार में देश की आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कम से कम 250 करोड़ रुपये तो अगम्य दिए जाने चाहिए थे लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण आयोग ने यह राशि 210 करोड़ रुपये निर्धारित की। पिछले दो वर्षों में देश को जिन वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ा उससे

[प्रो० एउ० नुइत हसन]

यह सदन भजी भांति अवगत है । मैं आशा करता हूं देश की स्थिति में शीघ्र सुधार होगा और हम थोड़ें .ही समय में यह नुकसान पूरा करने में सक्ष्य होंगे ।

केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 26 प्रतिशत धनराशि शिक्षा पर व्यक्ष की जाती है। यद्यपि वित्तीय कठिनाइयों के कारण शिक्षा के लिए दी जाने वाली राशि में कटौती ग्रवश्य की गई है फिर भी शिक्षा के उद्देश्य की उपेक्षा नहीं की गई है।

यह कहा जा रहा है कि हम ग्रभी भी शिक्षा की पुरानी साम्राज्यवादी पद्धति को जारी रखे हुए हैं ग्रौर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है ग्रौर यह भी कहा गया है कि इस देश ने कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई है। इस बारे में हमें दो तीन बातें ध्यान में रखनें होंगी।

सर्वप्रथम शिक्षा पद्वति में परिवर्तन एक निरन्तर प्रिक्रया है और शिक्षा सुत्र र भी एक निरन्तर प्रिक्रया है जिसे किसी निश्चित समय पर रोका नही जा सकता अतः यह मांग करते हुए कि शिक्षा की परिवर्तनशील परिस्थिय , वातावरण और देश की परिवर्तनशे ल आवश्यक । भ्रों के अनुकूल ढ़ाला जाये तब हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारी सम्पूर्ण शिक्षा पद्वति में विशेषतया उच्च शिक्षा के मामले में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है । आज अत्याकिक महत्वपूर्ण आवश्यकता राष्ट्र में आत्मविश्वास पैदा करने की है ताकि हम वास्तत में आत्म निर्भर बन सके ।

मैं सर्वप्रथम इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि उपनिवेशवादी प्रणाली के अन्त-गंत शिक्षा केवल सर्वोत्कृष्ट वर्ग के लोगो को हा प्राप्त थी। लेकिन आज शिक्षा देश की आम जनता तक पहुच गई है। वर्तमान आंकड़ों से पता चला है कि देश में 10 करोड़ बच्चे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है बीच अधूरी शिक्षा छोड़ने सम्बन्धी समस्या से मैं अवगत हूं इसके लिए हम एक नई दिशा देने पर विचार कर रहे है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा एक निर्णय लिया गया है। 'इस सदन ने भी एक निर्णय लिया है और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार के है यह राष्ट्रीय नीति वर्तमान परिवर्तनों के अनुरूप कियान्व की जा रही है। शिक्षा का प्रसार हुआ है।

जहां तक साक्षरता का सम्बन्ध है 1961 और 1971 के बीच शिशित लोगों की संख्या 10 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 16 करोड़ हो गई है 1971 में सभी ग्रायु वग के लोगों की जन्म से चार वर्ष तक ग्रायु वर्ग वाले बच्चों को छोड़कर साक्षरता 34 प्रतिशत है ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रायु वर्ग ग्रर्थात 10 वर्ष से 14 वर्ष तक जबिक बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिये, साक्षरता 50 प्रतिशत तक पहुच गई है। इसका यह ग्रर्थ हुग्रा कि यद्यपि ग्रध्री शिक्षा छोड़ देने की समस्या ग्रत्यन्त गम्भीर होने पर भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति व्यथ है ग्रन्यथा 14 वर्ष की ग्रायु वर्ग में साक्षरता की प्रतिशतता इतनी ग्रधिक नही बढ़ती 15 से 24 वर्ष तक ग्रायु वर्ग के लोगों में साक्षरता 48 प्रतिशत है। यदि हमारे स्कूल इसमें सहायता न करते तो इस प्रतिशतता का इतना विकास नहीं होता जनसंख्या सम्बन्धी ग्रैक्षिक संसाधनों के विकास में स्कूलों का भारी योगदान रहा है।

अब मैं उच्च शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत समस्याओं को लुंग। देश में 25,000 इंजीनियर स्नातक, 47,500 इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने तथा 12,500 चिकित्सा स्नातक एवम 15,000 कृषि स्नात्कों के लिये क्षमता है। अतः देश ने प्रौधोधिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में भारी प्रगति की है। हमारे पास अनुसंधानकर्ताओं का बहुत संवर्ग है। भारत का प्रोद्योगिकी तथा वैज्ञानिकी संवर्ग विश्व में तासरे स्थान पर हैं। हमारे इंजीनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक सरकारी कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालयों के स्नातकों ने ही इस देश के लिए बांध बनाये हैं बिजली घर बनाये हैं बड़े बड़े कारखाने और फार्म बनाये हैं इन्होंने ही विश्व में विद्यमान विशाल समाजिक सेवा पद्धति तैयार की है। इन उपलब्धियों के साथ कुछ असमानताएं भो हैं। कुछ एसे संस्थान है जो बास्तविक स्तर के नहीं हैं।

एक ग्रन्य समस्या शिक्षा ग्रौर रोजगार के सम्पर्क की है । यह ग्रत्यधिक महत्वपूर्ण मामला है। रोजगार के ग्रवसर उत्पन्न करना। राष्ट्र के समग्र ग्रार्थीक विकास से जुड़ा हुग्रा है। इसमें हमें कड़ी मेहनत ग्रौर दृढ़ निश्चय से कठोर परिश्रम करना होगा। तभी बेरोजगरी की समास्या हल करने में समर्थ होगे। लेकिन इसके साथ साथ जब तक रोजगार की सम्भावना की वृद्धि नहीं होगी उच्च शिक्षा के ग्रनियमित प्रसार ग्रौर विस्तार की ग्रनुमित देना उचित नहीं होगा। ग्रतः यह दोहरी वृद्धि है। पहले हम इस ग्रवधि में स्थापित सभी कालेजों को विक्तीय सहायता नहीं दे सकते ग्रौर दूसरे डिग्री प्राप्त करने वाले लोगों को उचित रोजगार नहीं मिलता है।

एक ग्रन्य समस्या शिक्षा की समवर्ती विषय बनाने की है। इस मामले पर मैं कोई निर्णय देने में ग्रसमर्थ हूं। इस पर तो प्रधान मंत्री राज्यों के मुख्य मंत्रियों से सलाह करके निर्णय ले सकती हैं। फिर भी मैं यह देखने का प्रयत्न करूगा कि क्या संविधान के ग्रन्तगंत शिक्षा सम्बन्धी परिवतनों ग्रीर सुधारां की गित तीच्र करने हेतु विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग की ग्रधिक शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग इन परिवर्तनों धीमी गित के सम्बन्ध में हमसे ग्रधिक चितित है। लेकिन जब हम कोई परिवर्तन लाने की बात करते हैं तो यहां सदन में मत वैभिन्न्य हो जाता है। बाह्य परीक्षा पद्धित से लाभ नहीं होगा। शिक्षा की परीधी से साम्प्रदायिकता, जातिभेद जैसे सिद्धांतों का उन्मूलन किया जाना चाहिये। हमें प्रितिक्यावादी शिक्षकों को भी बाहर निकालना है। हमें शिक्षकों पर विश्वास करना चाहिए। ग्रध्यापकों पर विश्वास किये बिना हम शिक्षा पद्धित में परिवर्तन लाने में समर्थ नहीं होंगे।

त्रमुशासन के प्रश्न पर भी यथेष्ठ बल दिया गया है। शिक्षा त्रमुशासन की एक प्रतिक्रिया है। शिक्षा मस्तिष्क, चरित्र, व्यक्तित्व तथा शरीर, सबको त्रमुशासन में करने वाली एक प्रतिया है ग्रातः सदस्यों ने ठीक ही त्रमुशासन की ग्रावश्यकता पर बल दिया है। मैं श्राशा करता हूं कि यह सन्देश सभी विश्वविद्यालयों ग्रीर कालेजों तक पहुंचेगा तथा प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए ग्रमुशासन ग्राह वान का हमारे सभी वर्ग ग्रीर शिक्षा संस्थान पालन करेंगे।

समाज के पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में भी उल्लेख किया गया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्यापघों की नियुक्ति को न्यूनतम अर्हताएं बढ़ाने का निर्णय लिया है । इसलिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए अध्यापको के पद आरक्षित रखें गये हैं । इसी प्रकार विश्वविद्यालाय अनुदान आयोग ने

प्रो० एस० नुरुल हसन]

यह सिफारिश भी की है कि शिक्षा संस्थानों में, विशेषकर उच्च शिक्षा में प्रतिष्ठित संस्थानों में ग्रनु सूचित जातियों ग्रीर ग्रनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए स्थान ग्रारक्षित किए जायें।

पांचवीं योजनाविध में विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग के लिए 5 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है। पटना विश्वविद्यालय के छात्राश्चास की दशा के बारे में भी उल्लेख किया गया है। विश्व-विद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग को इस स्थिति का पता है। मुझे ग्राशा है कि पांचवीं योजनाविध में पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास की दशा में सुधार कर दिया जायेगा ग्रीर यह समस्या हल हो जायेगी।

मौनी विद्यापीठ का मामला महाराष्ट्र सरकार की सोंप दिया गया है,क्योंकि यह महाराष्ट्र सरकार ग्रौर कोल्हापुर विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के ग्रन्तर्गत ग्राता है ।

भीमती रोजा देशपाँडे : क्या ग्राप उन्हें ग्रनुदान दे रहे हैं ?

प्रो० एस० नूरूल हसन: यह ग्रामीण उच्च शिक्षा संस्थान है। हम ग्रनुदान दे रहे हैं। निर्णय लिया गया है कि एक निश्चित तिथि के बाद उन्हें ग्रनुदान देना बन्द कर दिया जाना चाहिए और ये सभी पड़ोसी संस्थानों के साथ सम्बद्ध कर दिए जायेंगे। यह संस्थान ग्रव कोल्हापुर विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध हो गया है और हम उसे ग्रनुदान दे रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने पाठयक्रपों को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए इन का पूर्नीनमार्ण करने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख किया है। मैं इस मत से पूर्णतः सहमत हूं। मैंने आरम्भ में ही उल्लेख किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसके प्रति पूर्णरूपेण जागरूक है। यह कहना ठीक नहीं है कि जब से कोठारी आयोग ने सिफारिश पेश की हैं तब से कोई परिर्वत नहीं हुआ है। वह सभी सिफारिशें जिन्हें इस सदन ने स्वीकार कर लिया है तब से शिक्षा के राष्ट्रीय नीति संकल्प में शामिल की गई हैं; कियान्वित की जा रहीं हैं लेकिन यह सच है कि कियान्वियन की प्रक्रिया इतनी तेज नहीं है जितनी कि आप लोग चाहते हैं।

जामिया मि।लया की चर्चा भी की गई है। सरकार जामिया मिलिया की यथासम्भव सहायता देने का प्रयास करेगी ताकि वह फले फूले और उसी प्रकार राष्ट्र की सेवा करता रहे जैसा कि वह अतीत में करता आया है। हमें इस बात को भी घ्यान में रखना होगा कि यदि दिल्ली के कालेजों को उनके स्वीकृतबातों का 95 प्रतिशत दिया जाता है तो जामिया मिलिया को सरकार की ख्रोर से शत प्रतिशत दिया जाता है।

सुझाव दिया गया है कि जामिशा मिलिया को उर्दू विश्वविद्यालय बनाया जाये। इस विश्व-विद्यालय को अपनी डिग्निया देने का पूरा अधिकार है। इसमें पढ़ाई का माध्यम उर्दू है और परीक्षाओं का माध्यम भी उर्दू ही है। अन्य विश्वविद्यालयों जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान उर्दू माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति है।

उर्दू बोलने वालों की संख्या देश में बहुत है। ग्रतः एक विश्वविद्यालय को उर्दू विश्वविद्यालय की संज्ञा दे देने से उर्दू बोलने वाले लोगों की समस्या हल होने की सम्भावना नहीं है। ग्रतः सरकार ग्रीर विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग दोनों ही देश के सभी भागों में उर्दू के विकास को प्रोत्साहन दे रहे हैं। देश के कम से कम 21 विश्वविद्यालयों में उर्दू के स्नाहकोत्तर विभाग हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना में विद्यार्थी समुदाय को भी शामिल करने की बात कहें गई है। राष्ट्रीय सेवा योजना चौथी योजना के प्रारम्भ में शुरू की गई थी ग्रौर तब इसमें चालीस हजार विद्यार्थी थे ग्रौर ग्रब 1974-75 में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 1.6 लाख हो गई है। इस योजना का पुनः विस्तार ग्रौर विकास किया जा रहा है ग्रौर ग्राशा है जल्दी ही यह संख्या 2 लाख के लगभग पहुंच जायेगी।

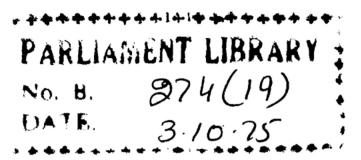
हम खेलकूद के विकास के सुझाव से पूर्णतः सहमत है। पिछले वर्ष ग्रखिल भारतीय खेलकूद परिषद् के कहने पर हमने खेलकूद को राज्य परिषदों ग्रौर खेलक्द के इंचार्ज मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें यह फैसला किया गया कि इस ग्रविध के दौरान प्रत्येक विकास खंड कम से कम 15,000 लोगों को एक खेल ग्रथवा शारीरिक शिक्षा गतिविधि में शामिल किया जाये। यह ग्राशा की जाती है कि हम इस विशेष कार्यक्रम को कियान्वित करने में समर्थ होंगे।

महिलाग्रों के दर्जे के सम्बन्ध में बनी समिति ने सिफारिश की है कि हमें लड़िकयों के लिए ृथक कालेज नहीं खोलने चाहियें बल्कि हमें उनके लिये ग्रधिक छात्रावास बनाने चाहिये। ग्रव ग्रायोग ने एक नई योजना बनाई है जिसके ग्रन्तर्गत कलेजों के लड़िकयों के लिए छात्रावास बनाने के लिए उदार सहायता दी जायेगी।

विश्वविद्यालयों का उद्देश्य रोजगार प्रधान शिक्षा प्रदान करना ही नहीं है बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य मन, शरीर श्रौर चरित्र का विकास करना है । हमें युवकों के श्रन्दर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 7 ग्रशस्त, 1975/16 श्रावण, 1897 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, the 7th August, 1975/Sravana 16, 1897 (Saka).



[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इस में अंग्रेजी/हिन्दी में दिथे गरे भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains
Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]